राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 74 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,15 सितम्बर 2021 , मूल्य रु. 1.50

पीएम मोदी बोले- 20वीं सदी की गलतियों को सुधार रहा 21वीं सदी का भारत

अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलीगढ़ के साथ प्रदेश तथा देश को दो बड़े तोहफे दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में दो घंटे के कार्यक्रम में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कारिडोर के अलीगढ़ नोड की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री ने अपने 40 मिनट के संबोधन में युवाओं को प्रेरणा देने के साथ उनमें जोश भी भरा। प्रधानमंत्री आगरा एयरपोर्ट पर विशेष प्लेन से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नमन करने के साथ ही उनकी कमी को काफी महमूस किया। पीएम मोदी ने युवाओं को राजा महेन्द्र प्रताप सिंह से परिचित कराने के साथ ही अलीगढ़ की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्य की काफी प्रशंसा करने के साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना तो बड़ी संख्या में निवेशक आने लगे। जिससे कि देश का गौरव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओडीओपी के तहत तालों व हार्डवेयर को नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे उद्योगों व एसएमएसई को विशेष लाभ होगा, अगले कुछ सालों में 900 करोड़ रुपया निवेश होगा। यूपी डिफेंस कारिडोर बड़े निवेश व रोजगार के बड़े अवसर लेकर आ रहा है यह तब होता है, जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अलीगढ़ व पश्चिमी यूपी के लिए बड़ा दिन है। आज राधाष्टमी है। हमारे संस्कार हैं, जब शुभ कार्य होता है तो अपने बड़े याद आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तो आज इस धरती के महान सपूत, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े। उन्होंने भारत के भविष्य की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपने देश-विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। राजा महेन्द्र प्रताप ने वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज को अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह ने ही दी थी। आज मां भारती के अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्याजंलि है। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छाशक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता सीखने को मिलती है। वह तो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक-एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई।

पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में कई महान व्यक्तित्वों ने अपना सब-कुछ खपा दिया। यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं को अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेल देव हों, या फिर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह हों। आज की पीढ़ी को इनसे परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसी कोशिशों को और गति दी गई है। साथियों आज देश के हर युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, उसे राजा के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। राजा की कुछ भी कर गुजरने की जीवटता हमें सीख देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे विचार को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को बधाई। यह विवि आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, इसके साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई और डिफेंस मैन्युफेक्क्रिंग से जुड़ी टेक्नालाजी व मैनपावर बनाने का सेंटर भी बनेगा। इस विवि मे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं से कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आएं तो राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को जरूर याद कर लेना। राजा जिस तरह एक लक्ष्य लेकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वह आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। आज मैं राजा महेन्द्रप्रताप जैसे के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है। साथियों, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के विकास की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कालेज अपने संसाधन से बनवाया। एएमयू को बड़ी जमीन दी।

आज 21 वीं सदी का भारत शिक्षा व कौशल के नए दौर की ओर बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विवि का निर्माण हो रहा है।आज जब आपसे बात कर रहा हं, तो मुझे एक और सेनानी गुजरात के सपूत श्याम जी का स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय राजा श्याम जी व लाला हरदयाल से मिलने यूरोप गए। उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वाचित सरकार के रूप मे देखने को मिला। जब मैं गुजरात का सीएंम था, तो मुझे श्याम जी की अस्थियों को भारत लाने में सफलता मिली। उनके अस्थि कलश हमें मां भारती के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि अभी तक लोग अपने घर की, अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था, तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे। तो अलीगढ़ से ताले के सेल्समैन थे, वह हर तीन महीने में हमारे गांव आते थे। वह ताला रख जाते थे, तीन महीने बाद पेमेंट ले जाते थे।

चार-छह दिन हमारे गांव में रुकते थे। जो पैसे वसूलकर लाते थे, वह मेरे पिता के पास रख जाते थे। गांव छोड़कर जाते थे, वह पिताजी से ले जाते थे। हम तो सीतापुर व अलीगढ़ शहर सुनते थे।

विजय रूपाणी के इस्तीफे पर शिवसेना का तंज, पूछा- क्या फट गया गुजरात मॉडल का गुब्बारा?

मुंबई। शिवसेना ने भारती जनता पार्टी द्वारा नेतृत्व परिवर्तन पर तंज कसा है। महाराष्ट्र में कभी साथ मिलकर सरकार चलाने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पूछा है कि क्या यही गुजरात मॉडल है? शिवसेना ने दावा किया है कि बीजेपी का गुजरात का विकास मॉडल धराशायी हो गया है।

शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा गया है कि गुजरात के लोग कोविड -19की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली के ढहने पर बेहद गुस्से में थे। भाजपा को भी यह एहसास हुआ कि प्रभावशाली पाटीदार जिस समुदाय से नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ताल्लुक रखते हैं, वह पार्टी से नाराज है। इस कारण से बीजेपी ने विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया।

भाजपा की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस में भी यही होता है और हमें इसे लोकतंत्र कहना होगा। अचानक नेतृत्व परिवर्तन के साथ, संपादकीय ने दावा किया कि गुजरात के विकास, शासन और लोकतंत्र के मॉडल का गुब्बारा अब फट गया है।

शिवसेना ने संपादकीय के जरिए सवाल पूछा है, पटेल को पिछले चार वर्षों में मंत्री भी नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर गुजरात वास्तव में प्रगति के रास्ते पर था, तो भाजपा ने रातों-रात अपना मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया?

संपादकीय में कहा गया है कि विकास के शोर-शराबे के बीच अगर अचानक नेतृत्व बदल जाता है तो लोग संदेह जताते हैं। उन्होंने पूछा, क्या यह गुजरात मॉडल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में पटेल को राज्य चुनावों (अगले साल दिसंबर में होने वाले) से पहले सबसे आगे रखना होगा? पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के कट्टर समर्थक हैं, जबकि रूपानी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त था।

शिवसेना का कहना है, रूपाणी को पटेल से बदलना एक आसान काम था। भाजपा को यकीन है कि बेरोजगारी, अहमदाबाद के पास कार निर्माता फोर्ड के संयंत्र सहित प्रमुख कारखानों के बंद होने के कारण उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान गुजरात की स्वास्थ्य प्रणाली ढह गई और लोग इससे बेहद नाराज हैं। संपादकीय में दावा किया गया है कि फोर्ड प्लांट को बंद करने से लगभग 40,000 लोगों की आजीविका चली गई है।

शिवसेना ने संपादकीय में कहा है, इसी तरह से उत्तराखंड, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कुछ ही दिन पहले बदले गए। मध्य प्रदेश में भी बदलाव किया जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, ऐसा प्रसारित हुआ है। कहां क्या बदलना है, यह उस पार्टी का अंदरूनी मसला है। रोटी घुमानी ही पड़ती है, परंतु जब किसी राज्य को विकास अथवा प्रगति का 'मॉडल' साबित करने के लिए उठापटक की जाती है, तब अचानक नेतृत्व बदलने से लोगों के मन में संदेह निर्माण होता है। भूपेंद्र पटेल पर अब गुजरात का भार आ गया है। वर्ष भर में विधानसभा के चुनाव हैं। पटेल को आगे रखकर नरेंद्र मोदी को ही लड़ना होगा। गुजरात मॉडल कहा जा रहा है, वो यही है क्या?

मप्र में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों की संख्या एक करोड़ पार

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना टीकाकरण की प्रतिदिन समीक्षा के उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या एक करोड़ से पार हो गई। एनएचएम की एमडी प्रियंका दास ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 5 करोड़ 21,53, 251 वैक्सीन टीके लगाए गए हैं। कुल टीकाकरण में 1,09,759 लोगों को दोनों डोज और 4 करोड़ 21 लाख 43 हजार 492 को पहली डोज लगाई जा चुकी है।

एक नज़र...

पं बंगाल के महाधिवक्ता किशोर दत्ता का इस्तीफा

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुछ निजी कारणों से अपना पद छोड़ा है। श्री दत्ता ने कहाकि पश्चिम बंगाल के लिए काम करना एक अद्भुत अनुभव रहा। इसबीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा, कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता द्वारा पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में दिए गए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है।

पदोन्नति में आरक्षण केस में राज्यवार होगी सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले में विस्तृत और राज्यवार सुनवाई की जाएगी। जस्टिसद्वय एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना व बीआर गवई की खंडपीठ ने कम से कम 133 याचिकाओं की सुनवाई में राज्य सरकारों को मुद्दों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट दो हफ्तों में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि वह देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर पांच अक्टूबर से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह पिछले फैसले में पहले से तय मुद्दों पर फिर से विचार नहीं करेगा।

सुष्मिता देव टीएमसी से राज्यसभा उम्मीदवार

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस छोड़ कर टीएमसी में शामिल हुई ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए प्रस्तावित उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा गए डॉ. मानस रंजन भुइयां के इस्तीफे के बाद खाली राज्यसभा की एक सीट पर चार अक्टूबर को उपचुनाव है। बता दें कि पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से दी थी।

75 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताई खुशी, बताया मील का पत्थर

नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में 75 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर खुशी जाहिर की. साथ ही उन्होंने लोगों से संकोच छोड़ने और टीका लगवाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश ने सोमवार को कोविड-19 टीके की 75 करोड़ खुराक देने का मील का पत्थर पार कर लिया. को-विन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सोमवार को शाम सात बजे तक 71 लाख से अधिक खुराकें दी गईं.

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'हमने कोविड-19 टीके की 75 करोड़ खुराक देने का मील का पत्थर पार कर लिया है, जबकि राष्ट्र हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है. स्वास्थ्य कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी लोगों की उनके असाधारण प्रयासों के लिए मैं प्रशंसा करता हूं' उपराष्ट्रपति ने लोगों से संदेह और झिझक दूर करके टीका लगवाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश सभी पात्र लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है.

कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75.22 करोड़ के पार- स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में रिकवरी रेट अब 97.58 प्रतिशत हो गया है. वहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 14,30,891 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 54,44,44,967 हो गया है. मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की 78,66,950 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75,22,38,324 हो गया है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 72.77 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक दी जा चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72,77,98,325 डोज सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की जा चुकी हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसके अलावा 1,60,75,000 वैक्सीन डोज पाइपलाइन में मौजूद हैं. आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, 4.49 करोड़ से ज्यादा (4,49,03,025) कोविड वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना है.

जब पीएम मोदी दुनिया के मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो हमें क्यों है शर्म :अमित शाह

नई दिल्ली। देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंद दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है। हिंदी दिवस के मौके पर आज ज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। इस मौके पर हिंदी के बारे में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री इंटरनेशल लेवल पर हिंदी बोल सकते हैं तो हमें किस बात पर शर्म आती है?

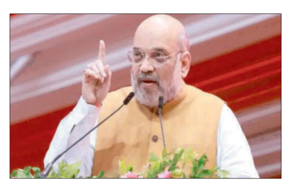

अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर होना केवल देश में उत्पादन करना नहीं है, हमें भाषाओं के साथ भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर पीएम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बोल सकते हैं, तो हमें किस बात पर शर्म आती है? वे दिन गए जब हिंदी में बात करना चिंता का विषय था।÷

इसके अलावा देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए अमित शाह ने ट्वीट किया, हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि मूल कार्यों में अपनी मातृभाषा के साथ राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने का संकल्प लें। मातृभाषा व राजभाषा के समन्वय में ही भारत की प्रगति समाहित है। आप सभी को 'हिंदी दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक चेतना व राष्ट्रीय एकता का मूल आधार होने के साथ-साथ प्राचीन सभ्यता व आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदी व सभी भारतीय भाषाओं के समांतर विकास के लिए निरंतर कटिबद्ध है।

अमरावती में नाव पलटने से 11 की मौत, आठ लापता

महाराष्ट्र में बड़ा हादसा

अमरावती (एजेसी)। महाराष्ट्र के अमरावती में एक बड़ा हादसा हुआ हैं। मंगलवार को वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों के मारे जाने की आशंका है और अभी भी आठ लोग लापता हैं। लोगों की तलाश अभी जारी हैं। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दलों ने अब तक तीन शव नदी से निकाले हैं जिनमें एक नाबालिग बच्ची का है।

उन्होंने बताया कि घटना हतराना गांव में सुबह करीब साढ़े दस बजे घटी जब 11 लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में पलट गई। अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नाव इतने सारे लोगों का बोझ नहीं सह सकी। बताया जा रहा हैं कि नाव में बैठे लोग एक पर्यटन स्थल को देखने आए हुए थे। हादसा होने के बाद पुलिस दल और स्थानीय विधायक देवेंद्र घटना स्थल पर पहुंचे।

कहर | जलपाईगुड़ी में 140 बच्चों को बुखार, दो शिशुओं की हुई मौत, इलाके में दहशत

पशिचम बंगाल में अनजान वायरस की दस्तक

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज बुखार का कहर जारी है। लगभग 140 बच्चों को तेज बुखार और पेचिश की शिकायत के साथ जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को दो शिशुओं की मौत की सूचना है।

सोमवार रात एक 6-7 महीने के बच्चे को उसके परिवार द्वारा सांस की तकलीफ और अन्य लक्षणों के साथ मैनागुड़ी अस्पताल लाया गया था। वहां उसकी मौत हो गई। इसके पहले मंगलवार की सुबह एक शिशु की मौत हुई थी। इस तरह से 24 घंटे में कुल दो शिशुओं की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर, बीमार बच्चों के रक्त नमूनों को कोलकाता भेजा गया है और कोलकाता से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जलपाईगुड़ी पहुंच गई है। विशेषज्ञों की इस चेतावनी के बीच यह घटना सामने आई है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक जोखिम हो सकती है। अधिकारी ने कहा, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अस्पताल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भर्ती करने से मना न किया जाए। स्थिति काफी चिंताजनक है।

एक दिन में 37 हजार लोग कोरोनामुक्त

नई दिल्ली, (एजेंसी) । देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बहुत अधिक रही जिससे सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.09 फीसदी रह गई है। देश में सोमवार को 78,66,950 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 75 करोड़ 22 लाख 38 हजार 324 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 25,404 नए मामलों की पुष्टि की गई, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 32 लाख 89 हजार 579 हो गया है। इस दौरान 37,127 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की 3,24,84,159 तीन करोड़ 24 लाख 84 हजार 159 हो गई है। सक्रिय मामले 12062 घटकर तीन लाख 62 हजार 207 रह गए हैं। इसी अवधि में 339 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,43,213 हो गया है।

दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की साजिश-टारगेट पर थे रामलीला और नवरात्र पर्व

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की तरफ से संचालित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसमें छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें दो पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि ये दो आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इन संदिग्धों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। स्पेशल सेल द्वारा गिरफ़्तार किये गए आतंकियों में से दो के नाम ओसामा और जिशान बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों के संपर्क अंडरवर्ल्ड से भी हैं। सूत्रों के मुताबिक, यूपी एटीएस के साथ मिलकर यूपी के प्रयागराज में छापेमारी की गई थी। स्पेशल सेल के इनपुट पर प्रयागराज के करेली से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से असलहे और बारूद बरामद होने की खबर है।

छह आतंकी गिरफ्तार

जान मोहम्मद

मो. अबु बकर

अमीर जावेद

मूलचंद (लाला)

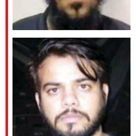

ओसामा और जीशान को ओमान के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था

रच रहे थे आतंकी हमले की साजिश

बताया जा रहा है कि पकड़ा गया टेरर मोड्यूल आईएसआई की सरपरस्ती में देश के बड़े शहरों में ब्लास्ट और आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक इक्ट्ठा किए गए थे। गिरफ्तार किए गए दो आतंकियों के डी कंपनी से संबंध है। बताया जा रहा है कि इस मॉड्यूल के बारे में खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क कई राज्यो में फैला है। इसके बाद रेड की गई और महाराष्ट्र निवासी एक आतंकी कोटा से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा दो दिल्ली से पकड़े गए और तीन को उत्तर प्रदेश एटीएस की मदद से पकड़ा गया।

दो आतंकी मस्कट के रास्ते पाक से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे

आतंकियों ने दो टीमें बनाई थी। अनीस इब्राहिम एक टीम को लीड कर रहा था और इनका फंडिंग का काम था। वहीं, लाला जो पकड़ा गया है वो अंडर वर्ल्ड का आदमी है। दूसरी टीम का काम भारत में त्योहारों के मौके पर देश भर में ब्लास्ट के लिए शहरों को चिन्हित करना था। इनकी योजना दिल्ली, उप्र और महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की थी। रामलीला व नवरात्र के प्रोग्राम टारगेट पर थे। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने बताया कि हमने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनमें से दो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। इनमें से दो पहले मस्कट गए फिर वहां बोट से इन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। इन्होंने बताया कि इनके साथ 14 लोग बांग्ला बोलने वाले थे। इन्हें एक फार्म हाउस में 15 दिनों तक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी।

पाक सैन्य अफसरों ने 15 दिन दी थी आतंकी ट्रेनिंग

ओसामा और जीशान पाकिस्तान में आतंकी पाकिस्तानी फौज के दो अफसरों ने किया था। उनके साथ एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक भी वहां मौजूद था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को पूछताछ में पता चला कि इसी साल अप्रैल में दोना कराची पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस काम को अंजाम देने में पाक एजेंसी आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने उन दोनों को ओमान से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए पानी के रास्ते का इस्तेमाल किया और वे बोट से पाकिस्तान गए थे। आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन दोनों को ओमान के रास्ते पाकिस्तान बुलाया था। कराची के एक इलाके में दोनों को पाकिस्तानी सेना के दो अफसरों जब्बार और हमज़ा ने आतंकी ट्रेनिंग दी थी। वहां उन फौजी अफसरों के साथ आसिफ़ नाम का एक पाकिस्तानी शख्स और मौजूद था।

ओडिशा में जासूसी करते डीआरडीओ के चार कर्मी पकड़े गए

ओडिशा के बालासोर से पुलिस ने डीआरडीओ के चार कर्मचारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। चांदीपुर सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये चारों कर्मचारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंट्स को भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट मोटी रकम दे रहे थे। गिरफ्तार कर्मचारियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दूसरी धाराएं लगाई गई हैं।

सार समाचार

ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 15 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में कोविड-19 के 22 नए मामले आने के बाद लॉकडाउन को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, सिडनी में वायरस के 'डेल्टा' स्वरूप का एक मामला सामने आने बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में 12 अगस्त से लॉकडाउन लगा है। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री एंड्रयू बर्र ने मंगलवार को बताया कि कैनबरा के लॉकडाउन को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया जाएगा। कैनबरा न्यू साउथ वेल्स राज्य से घिरा हुआ है, जहां ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 'डेल्टा' स्वरूप के मामले सामने आए थे। कैनबरा में 'डेल्टा' स्वरूप आने से पहले, 4,30,000 लोगों के शहर में 10 जुलाई, 2020 से कोरोना वायरस सामुदायिक संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था।

यूएनएचआरसी प्रमुख ने जम्मू-कश्मीर में संचार सेवाओं पर अस्थायी पाबंदी को लेकर भारत की आचोलना की

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू-कश्मीर में बार-बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को सोमवार को चिंताजनक बताया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में उद्घाटन वक्तव्य में, बेशलेट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपायों के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और भविष्य में तनाव व असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर बार बार पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला जारी है जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं। साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है। बेशलेट ने कहा, पूरे भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम का उपयोग चिंताजनक है। जम्मू-कश्मीर में ऐसे सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बेशलेट की टिप्पणियों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत ने अतीत में कई मौकों पर जम्मू-कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की आलोचनाओं को दृढ़ता से खारिज किया है।

राष्ट्रपति पुतिन खुद को करेंगे सेल्फ-आईसोलेट

मॉस्को। क्रेमलिन ने मंगलवार को एक बयान में कहा,रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने इनर सर्कल में पाए गए कोविड -19 मामलों के कारण एक निश्चित अवधि के लिए सेल्फ-आईसोलेशन करेंगे। टास न्यूज एजेंसी ने बयान के कहा, (राष्ट्रपति) व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके इनर सर्कल में पहचाने गए कोरोनावायरस मामलों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए खुद को सेल्फ-आईसोलेशन करना पड़ेगा। इसके चलते, पुतिन इस सप्ताह दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सऊदी के नेतृत्व वाले हवाई हमलों में 43 हाउती मारे गए

सना। एक सैन्य सूत्र ने मंगलवार को जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में यमन के मारिब प्रांत में सऊदी के नेतृत्व वाले हवाई हमलों में कम से कम 43 हाउती विद्रोही मारे गए हैं। मारिब में सशस्त्र बलों के मीडिया सेंटर के सूत्र ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि हवाई हमले में सिरवाह जिले में अग्रिम मोर्चे पर विद्रोहियों की चौकियों, सभाओं और अतिरिक्त सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 43 लोग मारे गए और हथियारों से लैस नौ वाहनों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा, हवाई हमले विद्रोहियों द्वारा (यमनी) सेना के मोर्चे पर अग्रिम मोर्चे पर शुरू किए गए जमीनी हमलों की प्रतिक्रिया थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार समर्थक सशस्त्र बलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। हाउती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी ने अधिक विवरण दिए बिना ही सिरवाह जिले में 19 सऊदी नेतृत्व वाले हवाई हमलों की सूचना दी। पिछले हफ्ते, हाउतीयों ने दक्षिण-पश्चिमी मारिब में राहाबा जिले पर नियंत्रण कर लिया था। फरवरी में, हाउती मिलिशिया ने तेल-समृद्ध प्रांत, सऊदी समर्थित यमनी सरकार के अंतिम उत्तरी गढ़ पर नियंत्रण करने के प्रयास में मारिब पर एक बड़ा हमला किया था।

ट्रम्प के समर्थन में रैली के लिए कैपिटल के चारों ओर सुरक्षा चाकचौबंद

वाशिंगटन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में शनिवार को होने वाली दक्षिणपंथी रैली से पहले यूएस कैपिटल के चारों ओर घेराव किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी ने कैपिटल पुलिस प्रमुख थॉमस मंगर के हवाले से सोमवार को संवाददाताओं से कहा, ये घेराव एक या दो दिन पहले बढ़ जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कम हो जाएगा। शनिवार की रैली, जिसका शीर्षक जस्टिस फॉर जे6 है, का उद्देश्य 6 जनवरी के कैपिटल हमले के मद्देनजर सैकड़ों दंगाइयों की गिरफ्तारी का विरोध करना है। इससे पहले सोमवार को, कैपिटल पुलिस अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी मुख्यालय के बाहर एक संगीन और एक हथियार रखने के आरोप में एक 44 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कैपिटल बिल्डिंग के दक्षिण में स्थित है। वाशिंगटन में दोनों चीजे अवैध हैं। कैपिटल पुलिस के अनुसार, वह व्यक्ति श्वेत वर्चस्ववादी नारों से लदे ट्रक को चला रहा था, और उसने कहा कि वह गश्ती पर था। कैपिटल में घातक भगदड़ के बाद के दिनों में मूल कैपिटल सुरक्षा बढ़ाई गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए 2020 के चुनाव परिणामों को प्रमाणित करने से कांग्रेस को रोकने के प्रयास में 6 जनवरी को कैपिटल का उल्लंघन करने वाले ट्रम्प समर्थकों की भीड़ का सामना करने पर कुछ 140 पुलिस अधिकारी कथित तौर पर घायल हो गए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में बुलाई क्वाड की अहम बैठक तो चीन को लगी मिर्ची, कहा- हमें न किया जाए टारगेट

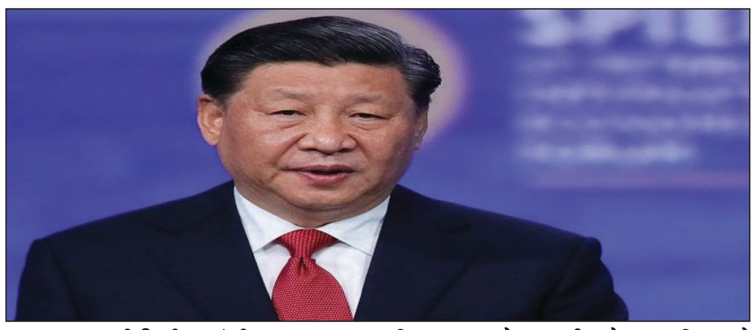

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

अमेरिका और चीन के बीच रिश्तो में उतार-चढ़ाव जारी है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वाशिंगटन में क्वाड देशों की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक के 24 सितंबर को आयोजित होगी। प्रत्यक्ष तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जो बाइडन करेंगे। इसी को लेकर अब चीन भड़क गया है। आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर निशाना साधते हुए चीन ने कहा कि दूसरे देशों को टारगेट करने के लिए गुटबाजी काम नहीं आएगी और इसका कोई भविष्य नहीं है। क्वाड को लेकर पूछे गए सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि देशों के बीच सहयोग के जरिए तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

चीन ने क्या कहा

झाओ लिजियान ने कहा कि चीन का मानना है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग ढांचे को समय की प्रवृत्ति के साथ होना चाहिए और क्षेत्र के देशों के बीच आपसी विश्वास तथा सहयोग के अनुकूल होना चाहिए। इसके जरिए किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लिजियान ने कहा कि दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए 'गुटबाजी' नहीं होनी चाहिए और ये तरीके काम नहीं करेंगे तथा इनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा, ''मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि चीन न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन है, बल्कि यह शांति की रक्षा करने वाली मुख्य शक्ति भी है।'' साथ ही कहा कि चीन की उन्नति दुनिया में ''शांति के लिए अच्छी खबर'' है। लिजियान ने कहा, ''संबंधित देशों को शीत युद्ध वाली मानसिकता और संकीर्ण सोच वाली भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की अवधारणा को त्याग देना चाहिए। सही ढंग से देखना चाहिए और क्षेत्र में लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए तथा क्षेत्रीय एकजुटता एवं सहयोग के लिए और अधिक काम करना चाहिए।''

क्या है क्वाड

आपको बता दें कि नवंबर 2017 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखने के संबंध में नयी रणनीति विकसित करने के लिए क्वाड के गठन के लंबित प्रस्ताव को आकार दिया था। मार्च में राष्ट्रपति बाइडन ने डिजिटल तरीके से क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच क्वाड का शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के निवर्तमान प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा हिस्सा लेंगे।

ब्रिटेन में 12 से 15 साल के स्कूली बच्चों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जाएगी

लंदन। ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की है कि 12 से 15 साल के स्कूली बच्चों को अगले सप्ताह से फाइजर/बायोएनटेक के कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जाएगी। देश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बच्चों के लिए टीके को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग (डीएचएससी) ने सोमवार

शाम को कहा कि मंत्रियों ने ब्रिटेन के चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श को स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) अब स्कूलों के आधार पर टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी कर रही है।

एनएचएस ने कहा कि यह टीकाकरण भी एचपीवी और डिप्थीरिया, टिटनेस तथा पोलियो समेत अन्य टीकों के सफल मॉडल को अपना कर किया जाएगा जिसमें डॉक्टर और फार्मेसी सहभागिता करेंगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा, ''मैंने 12 से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगाने की मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिश को मान लिया है। यह बच्चों को स्कूलों में कोविड-19 से बचाने और कक्षाएं बहाल करने की दिशा में किया जा रहा है।

स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने दूसरे स्वतंत्रता जनमत संग्रह पर किया विचार

लंदन (एजेंसी)।

स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने कहा कि यदि कोविड -19 महामारी नियंत्रण में रहती है तो उनकी पार्टी 2023 के अंत तक ब्रिटेन से स्वतंत्रता पर एक और कानूनी जनमत संग्रह कराने पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के सम्मेलन में दिए गए एक भाषण में स्टर्जन ने दूसरे स्कॉटिश स्वतंत्रता जनमत संग्रह का आहवान किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से सहयोग की भावना से सहमत होने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि मई में स्कॉटलैंड में लोगों ने एक नई स्कॉटिश संसद का चुनाव किया, जिसके पास स्वतंत्रता जनमत संग्रह के पक्ष में स्पष्ट और पर्याप्त बहुमत है। उन्होंने कहा, जैसे ही हम कोरोना वायरस महामारी से निकलेंगे तब ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो आने वाले दशकों के लिए स्कॉटलैंड को नया आकार देंगे। इसलिए हमें तय करना होगा कि उन निर्णयों को कौन लेगा, स्कॉटलैंड के लोग या सरकारें जिन्हें हम वेस्टमिंस्टर में वोट नहीं देते हैं।

उन्होंने अपने भाषण में कहा, यह वह विकल्प है जिसका हम संसद के इस कार्यकाल के भीतर एक कानूनी जनमत संग्रह में स्कॉटिश लोगों की पेशकश करने का इरादा रखते हैं। स्टर्जन ने कहा कि यह वेस्टमिंस्टर सरकार पर निर्भर नहीं है, जिसके पास स्कॉटलैंड में सिर्फ छह सांसद हैं, जो यहां रहने वाले लोगों की सहमति के बिना हमारे भविष्य का फैसला करते हैं। रविवार को स्काई न्यूज से बात करते हुए, स्टर्जन ने कहा कि वह संक्रमण का एक सटीक स्तर निर्धारित नहीं कर सकती, लेकिन आप कोविड स्थिति को नियंत्रण में जरूर देखना चाहेंगे।

एसएनपी सम्मेलन ने कोविड -19 संकट के बाद जल्द से जल्द एक और स्वतंत्रता जनमत संग्रह के समय के लिए स्कॉटिश सरकार की योजनाओं का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खत्म होने के बारे में तारीख डेटा-संचालित मानदंड द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

बता दें कि पिछली बार 2014 में एक स्कॉटिश स्वतंत्रता जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें 55

प्रतिशत मतदाताओं ने ब्रिटेन में रहने का समर्थन किया था। मई में स्कॉटिश संसदीय चुनाव में स्टर्जन की पार्टी ने लगातार चौथी जीत हासिल करने के तुरंत बाद, महामारी संकट बीत जाने पर दूसरे स्वतंत्रता जनमत संग्रह के लिए जोर देने का वादा किया। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले कह चुके हैं कि वह दूसरे स्वतंत्रता जनमत संग्रह को मंजूरी नहीं देंगे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया, जहां अब तालिबान का शासन है। विदेश कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश कार्यालय के अनुसार,अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर डिजिटल माध्यम से जिनेवा में आयोजित उच्च स्तर की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कुरैशी ने आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दोनों के मामले में अफगान लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने विकासात्मक साझेदारी को नवीकृत करने, राष्ट्र निर्माण का समर्थन करने और अफगान लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कुरैशी ने दुनिया को पाकिस्तान द्वारा जारी मानवीय सहायता के

कई तरीकों से अवगत कराया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को निकालने और स्थानांतरित करने की सुविधा, राहत सामग्री की डिलीवरी के लिए एक मानवीय गलियारे की स्थापना और हवाई व जमीनी मार्ग केमाध्यम से अफगान लोगों की सहायता शामिल है। बैठक की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की, जिसमें ओसीएचए, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी, यूएनएफपीए, यूनएचएचसीआर और आईसीआरसी सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों ने शिरकत की। बैठक में स्विट्जरलैंड, कतर, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, तुर्की और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के कई मंत्रियों ने भी भाग लिया।

अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए यूरोपीय संघ प्रणाली में ऑडिटर्स ने खामियों को किया उजागर

ब्रसेल्स (एजेंसी)।

यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स (ईसीए) की एक विशेष रिपोर्ट में अवैध रूप से ब्लॉक में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) और गैर-यूरोपीय संघ के देशों के बीच सहयोग में अक्षमताओं को चिह्नित किया गया है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, नतीजतन, यूरोपीय संघ केवल तीसरे देशों के साथ दोबारा प्रवेश समझौतों के समापन में सीमित प्रगति हासिल करने में कामयाब रहा है।

विशेष रिपोर्ट के अनुसार, 2015-2020 की अवधि के दौरान, जिसकी समीक्षा की गई थी, ब्लॉक की कार्रवाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुव्यवस्थित नहीं किया गया कि गैर-यूरोपीय संघ के देश व्यवहार में अपने दोबारा प्रवेश दायित्वों का पालन करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया कि 2008 से सभी वर्ष, लगभग 500,000 गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों को ब्लॉक छोड़ने का आदेश दिया गया था क्योंकि वे इसमें प्रवेश कर चुके थे या बिना प्राधिकरण के रह रहे थे।

हालांकि, पांच में से एक से भी कम वास्तव में यूरोप के बाहर अपने देशों में लौट आए। ईसीए ने कहा कि अनियमित प्रवासियों की कम संख्या का एक कारण प्रवासियों के मूल देशों के साथ सहयोग करने में कठिनाई है। इसने कहा कि यूरोपीय संघ ने 18 कानूनी रूप से बाध्यकारी दोबारा प्रवेश समझौतों को समाप्त कर दिया है और छह अन्य देशों के साथ औपचारिक रूप से चर्चा शुरू कर दी है।

हाल ही में, इसने रिटर्न और प्रवेश के लिए छह गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्थाओं पर भी बातचीत की है।

भेदभाव मुक्त समाज चाहते हैं जो विविधता का सम्मान करते हैं : एडानो

टोक्यो (एजेंसी)।

विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान (सीडीपीजे) के नेता युकिओ एडानो ने कहा कि वह एक भेदभाव मुक्त समाज का एहसास करना चाहते हैं जो विविधता का सम्मान करते हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि पार्टी आम चुनाव जीतने पर इसे लागू करेगी, जिसमें विवाहित जोड़ों को अपने उपनाम अलग रखने का विकल्प भी शामिल है।

न्याय मंत्रालय के अनुसार, जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास विवाहित जोड़ों को उपनाम साझा करने के लिए मजबूर करने वाला कानून है, हालांकि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सिफारिश की है कि देश को इस प्रणाली को बदलना चाहिए।

सीडीपीजे का उद्देश्य यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून पेश करना, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करना और लिंग, राष्ट्रीयता और विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अलावा, इसने जापान की आव्रजन प्रणाली की समीक्षा करने की योजना बनाई। नीतियों की घोषणा 29 सितंबर को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व की दौड़ के रूप में आती है, जिसमें जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के उत्तराधिकारी को केंद्र में रखा जाएगा।

एडानो ने कहा, एलडीपी पर (इस तरह के बदलावों के लिए) अडिग विरोध का बोलबाला है। जो कोई भी इसका अध्यक्ष बनता है, वह उन्हें महसूस नहीं कर सकता है। हमें सत्ता परिवर्तन को पूरा करना चाहिए।सीडीपीजे ने पिछले हफ्ते अपना पहला वादा जारी किया, जिसमें कोविड -19 महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक अनुपूरक बजट पर काम करना, उपभोग कर की दर को कम करना, परमाणु ऊर्जा के बिना एक शून्य-कार्बन समाज प्राप्त करना, न्यूनतम वेतन बढ़ाना और विरोध करना शामिल है। चूंकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की शर्तें 21 अक्टूबर को समाप्त हो रही हैं, इसलिए जापान में आम चुनाव आने वाले महीनों में होंगे।

स्वच्छ ऊर्जा की खातिर अमेरिका-भारत के सहयोग को मजबूत करने के लिए विधेयक पेश

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब दोनों देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं तो उसके ''सकारात्मक परिणाम'' सामने आते हैं। विदेशी संबंध मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज ने भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए एक विधेयक 'द प्रायोरिटाइजिंग क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कॉपरेशन विद इंडिया एक्ट ऑफ 2021' पेश किया।

जलवायु संबंधी मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

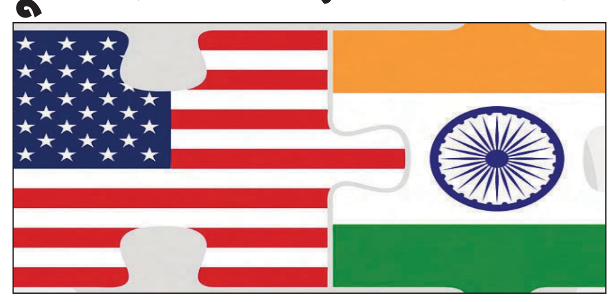

के विशेष दूत जॉन केरी के नई दिल्ली में 'क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग' (सीएएफएमडी)' शुरू करने के एक दिन बाद यह विधेयक पेश किया गया। मेनेंडेज ने कहा, ''जलवायु परिवर्तन के साझा खतरे और भारत में बिजली की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, अमेरिका-भारत को स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।

इस दिशा में, मैं इस विधेयक को पेश कर रहा हूं, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे जब हमारे देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप' की स्थापना करके, हम न केवल अमेरिका और भारत की सरकार के बीच, बल्कि हमारे विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्रों के बीच भी एक सफल साझेदारी की नींव रख रहे हैं। मुझे भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के इस प्रयास का नेतृत्व करने पर गर्व है।

ड्रैगन का खूंखार प्लान! ताइवान, अरुणाचल और दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे का देख रहा सपना

बीजिंग। (एजेंसी)।

पूर्वी लद्दाख को हथियाने की फिराक में बैठा चीन दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने के लिए एक रणनीति बनाई है। दरअसल, चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि चीन के अलावा तालिवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। माना जा रहा है कि इन हिस्सों में प्राकृतिक तेल और गैस के असीमित भंडार हो सकते हैं।

ऐसे में चीन लगातार दक्षिण चीन सागर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की फिराक में जुटा रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जो योजना तैयार की है उसके मुताबिक वो 2030 तक दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा।

ताइवान पर भी होगा कब्जा

अपने वर्चस्व को बढ़ाने की लगातार कोशिशें करना वाला चीन साल 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चीन विस्तारवादी योजना के तहत अपने आस-पास के तमाम मुल्कों पर अपनी पैठ बनाना चाहता है। ताइवान लगातार चीन का विरोध करता रहा है इसके बावजूद चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में साल 2025 तक चीन ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है।

अरुणाचल पर भी निगाहें

चीन अपना दावा अक्साई चीन, लद्दाख के भाग, उत्तराखंड के कुछ भाग और पूरे अरूणाचल प्रदेश पर करता है। ताइवान के बाद चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पर होगी। साल 2025 में चीन पर कब्जा करने के बाद 2040 में अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे पर ले लेगा। दरअसल, दुनियाभर में चीनी वेबसाइट सोहू द्वारा साल 2013 में छापी गई एक रिपोर्ट फिर से वायरल हो रही है। जिसमें यह तमाम दावे किए गए थे।

दक्षिण चीन सागर पर होगा कब्जा

चीन ताइवान पर कब्जा करने के बाद भी नहीं रुकने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के बाद चीन वियतनाम और फिलीपिंस को हराकर साल 2030 तक दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और फिर साल 2035 से 2040 के बीच में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझाकर अरुणाचल में कब्जा करेगा। फिर 2045 तक जापान के सेनकाकू द्वीप समूह, 2050 तक मंगोलिया, 2060 तक दक्षिणी रूस के कई इलाकों में कब्जा कर लेगा।

टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने केजरीवाल से की मुलाकात

बजरंग पुनिया ने देश को किया गौरवांवित : केजरीवाल

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)।

टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने मंगलवार को अपने कोच सतपाल सिंह के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की।

भविष्य में देश के लिए ढ़ेर सारे मेडल लाने की दीं शुभकामनाएं

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई दी और भविष्य में देश के लिए ढ़ेर सारे मेडल लाने की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि बजरंग पुनिया ने भारत को गौरवांवित किया है और हम सभी को गौरवांवित किया है। वे लाखों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत हैं। उनका प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा और अधिक से अधिक मेडल लाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की स्थापना की है, ताकि हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ढ़ेर सारे खिलाड़ी पैदा किए जा सकें। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने अपने कोच सतपाल सिंह के साथ मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कई साल से ट्रेनिंग कर रहें और दिल्ली के लिए खेलने वाले बजरंग पुनिया को सीएम अरविंद केजरीवाल ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी और आने वाले समय में भारत के लिए ढ़ेर सारे मेडल लाने के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक की अपनी यात्रा के बारे में बताया और अपने अनुभव को साझा किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजरंग पुनिया ने जो उपलब्धि हासिल की है, उस पर पूरे देश को गर्व है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने की है योजना : केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करह कहा, आज मेरे आवास पर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया से मिलकर खुशी हुई। बजरंग ने भारत को गौरवान्वित किया है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। आप लाखों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत हैं। टोक्यो ओलंपिक में कास्य विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। उनका यह प्रदर्शन देश के भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रेरणा देने का काम करेगा और उन्हें भी अधिक से अधिक मेडल जीत कर लाने के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और खिलाड़ियों को मदद देने के लिए हमेशा तत्पर रही है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की स्थापना की है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम ढेर सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करना चाहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में अधिक से अधिक मेडल जीतकर भारत को गर्वांवित कर सकें।

पुनिया अब 2024 का लक्ष्य लेकर कर रहे हैं तैयारियां: सतपाल सिंह

बजरंग पुनिया के कोच सतपाल सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया अब 2024 का लक्ष्य लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। युवा ही हमारे देश की संपत्ति हैं। जब बररंग पुनिया जैसे बच्चे आगे आएंगे, तभी दूसरे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। बजरंग पुनिया दिल्ली से ही रष्ट्रीय स्तर पर खेलते रहे हैं। इसलिए वह आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनका आर्शीवाद लेने आए थे। मुख्यमंत्री ने मेरी ट्रेनिंग के बारे में पूछा कि कहां पर ट्रेनिंग चल रही है और आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा की। मैंने छत्रसाल स्टेडियम में कई साल तक ट्रेनिंग की है। दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बनवा रही है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने की योजना है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने देश के लिए खेलने और ढेर सारे मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अरविंद केजरीवाल ने फ्रंटलाइन वर्कर की पत्नी को सौंपा 10 लाख की आर्थिक मदद का चेक

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान डॉ. अमित सिंह दामिया की कार्डियक अरेस्ट से निधन होने पर उनकी पत्नी मनमीत अलंग को सहानुभूति के आधार पर आज आर्थिक मदद के तौर पर दस लाख रुपए का चेक सौंपा. स्व. डॉ. अमित सिंह दामिया के परिवार को यह आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की गई है. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ हमेशा खड़े हैं. हमें स्वर्गीय डॉ. अमित सिंह की सेवा पर बहुत गर्व है. हम उनकी जिंदगी वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को थोड़ी मदद मिल जाएगी.

स्वर्गीय डॉ. अमित सिंह दामिया की पत्नी मनमीत अलंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान स्व. डॉ. अमित सिंह की पत्नी के साथ उनकी मां और बच्चा साथ में थे. केजरीवाल ने स्वर्गीय डॉ. अमित सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना के दौरान लगातार ड्यूटी की और पूरी लगन से कोरोना मरीजों की सेवा की. मैं उनके परिवार से आज मिला और परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 10 लाख रुपए का चेक सौंपा. यह हमारी तरफ से मदद का एक छोटा सा प्रयास है.

वहीं, स्व. डॉ. अमित सिंह दायमा की पत्नी मनमीत अलंग ने आर्थिक मदद देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली सरकार मेरे बुरे वक्त में साथ खड़ी रही. इसके लिए सीएम केजरीवाल की बहुत आभारी हूं.

स्वर्गीय डॉ. अमित सिंह दामिया स्वामी विवेकानंद अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग में अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में तैनात थे। वह कोरोना की ड्यूटी पर थे और ड्यूटी के दौरान ही उन्हें 13 मई 2021 को कार्डियक अरेस्ट का अटैक आया था.

उन्हें हरियाणा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया. वह कोरोना काल के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे थे और पूरे लगन के साथ कोरोना मरीजों की सेवा की. परिवार में कमाने वाले वह अकेले थे. उनके परिवार में पत्नी, मां और एक बच्चा है। परिवार किराए के मकान में रहता है. बताते चलें कि दिल्ली के विकासपुरी एरिया निवासी स्वर्गीय डॉ. अमित सिंह दामिया स्वामी विवेकानंद अस्पताल में अनुबंध पर वरिष्ठ रेजिडेंट के तौर पर तैनात थे. वह कोविड-19 काल में लगातार ड्यूटी की थी.

संक्षिप्त खबर

पूर्वी दिल्ली निगम ने किया हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को हिंदी दिवस के मौके पर हिन्दी प्रतियोगिता-2021 के विजेताओं को नकद राशि, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, उपमहापौर किरण वैद्य, वरिष्ठ पार्षद, शशि चांदना, बबीता खन्ना, निर्मला कुमारी, अपर आयुक्त, शिल्पा शिंदे व अल्का शर्मा और निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हिन्दी के प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है, हिन्दी व्यक्ति को अशिक्षा से ज्ञान की ओर ले जाने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी भाषाएं सम्मानीय है लेकिन राजभाषा के प्रति हमारे दिल में अतिरिक्त सम्मान होना स्वाभाविक है। महापौर ने कहा कि हम हिंदी में जितना अधिक काम करेंगे, उतनी ही अधिक कुशलता से हम अपने कार्य कर सकेंगे। अग्रवाल ने कहा कि आज अमेरिका समेत दुनिया के सभी बड़े मुल्कों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। महापौर ने हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी। उपमहापौर किरण वैद्य ने कहा कि हिन्दी जनमानस की भाषा है जो भारत के लोगों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग काम करते हैं लेकिन हिंदी के प्रति उनका अनुराग सराहनीय है। अपर आयुक्त शिल्पा शिंदे ने गृह मंत्री, अमित शाह का हिंदी दिवस पर संदेश पढ़कर सुनाया वहीं, अपर आयुक्त, अल्का शर्मा ने मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के संदेश का वाचन किया।

अवैध मीट की दुकानों पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सुंदर नगरी क्षेत्र में मीट की अवैध दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध दुकानों से तख्त, जाल, ड्रम आदि सामान नष्ट किया गया। कार्रवाई की दौरान पुलिस बल की भी मदद ली गई और जेसीबी मशीन से सामान हटाए गए। कार्रवाई के दौरान नियमानुसार कई सामान जब्त किए गए।

सब्जीमंडी इमारत हादसा मामले में एक गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सब्जीमंडी इलाके में इमारत हादसे के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान मोहक अरोड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सब्जीमंडी इलाके में इमारत गिरने के मामले में मोहक अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की 288/304 /34 धाराओं के तहत कल प्राथमिकी दर्ज की थी। गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार एक जर्जर इमारत जमींदोज हो गई थी। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई थी।

खोरी गांव में पुनर्वास की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2022 तक पूरी हो सकेगी : नगर निगम

नई दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम स्थित खोरी गांव में पुनर्वास की प्रक्रिया अगले वर्ष 30 अप्रैल तक पूरी हो सकेगी। निगम ने उच्चतम न्यायालय में सूचित किया है कि वह 30 अप्रैल 2022 तक खोरी गांव विध्वंस के संबंध में पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी प्रयास करेगा, जिसमें पात्र आवेदकों को फ्लैटों का कब्जा सौंपना भी शामिल है।

आरोपित ने फेसबुक पर लिख दिया हत्या का कुबूलनामा!

नई दिल्ली । नेशनल कान्फ्रेंस के जम्मू से सिख नेता व पूर्व विधान पार्षद त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्या आरोपित हरप्रीत सिंह खालसा व हरमीत सिंह खालसा के बारे में दिल्ली पुलिस को कोई सटीक सुराग नहीं मिल पा रहा है। इस बीच पश्चिमी व बाहरी जिले की पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच व स्पेशल सेल की कई टीम जम्मू में पिछले कई दिनों से डेरा डाल दोनों को दबोचने के लिए हर संभावित ठिकाने पर खाक छान रही है।

गत शनिवार को हरमीत सिंह के फेसबुक पेज पर जो छह पन्ने का पोस्ट किया गया था, वह एक तरह से हत्या का कबूलनामा ही लग रहा है। हालांकि, पुलिस इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे उक्त तथ्य को अभी सही नहीं मान रही है, लेकिन पोस्ट में विस्तार से जिस तरह की बातें लिखी गई हैं उससे ऐसा लगता है कि उक्त पत्र को हरमीत ने ही लिखा है। हरप्रीत के परिवार में मां व बहन है। कई साल पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि हरप्रीत अपनी मां व बहन से कोई संपर्क नहीं रखता था। इस कारण ही स्वजन से हरप्रीत के बारे में सुराग नहीं लग पाया। हरमीत के स्वजन से भी पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

इन बातों को सुन गुस्से में आया हरमीत- हरमीत के फेसबुक पोस्ट पर छठे पन्ने में स्पेशल नोट करके पांच बातें लिखी हुई है। हरमीत के नाम से लिखे नोट में कहा गया है कि उसे सब से ज्यादा गुस्सा तब आया जब वजीर ने कहा कि उसने चोपड़ा परिवार को मरवा दिया है। बिल्ला व डिग्यिाना के तीन लड़कों को भी मार दिया है साथ ही पप्पी सिंबल वाले को मरवा देने की बात कही। वजीर से हरप्रीत को उसने यह कहते हुए भी सुना कि अब तक उसने सौ के करीब लोगों को मारवा दिया है।

प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में केजरीवाल सरकार

विंटर एक्शन प्लान बनाने को लेकर पर्यावरण मंत्री ने की समीक्षा बैठक

(रविशंकर तिवारी)

नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर मंगलवार को सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को 21 सितम्बर तक अपनी-अपनी कार्य योजना बनाकर पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों को निर्धारित 10 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार हम दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार करेंगे। साथ ही, जमीनी स्तर पर काम करने वाले इंजीनियर, एई और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सरकार के जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलेंगे।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से जल्द मिलेंगे केजरीवाल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पराली पर बायो डि-कंपोजर के प्रयोग को लेकर आई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट सौंपेंगे और उनसे अन्य राज्यों में लागू कराने की मांग करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

पराली की समस्या से निपटने के लिए की है तैयारी

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली की समस्या से निपटने के लिए विकास विभाग को एक्शन प्लान बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। विकास विभाग के अंतर्गत कृषि विभाग आता है। विभाग से पूछा गया है कि दिल्ली के अंदर पैदा होने वाली पराली से निपटने के लिए इस साल टाइम लाइन और एक्शन प्लान क्या होगा ? वहीं, धूल प्रदूषण रोकने के लिए तीनों एमसीडी, कंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को जिम्मेदारी गई है। साथ ही, सभी निर्माण एजेंसियों को खासतौर से चार बिंदुओं पर अपना एक्शन प्लान बनाने के लिए लक्ष्य दिया गया। पहला, डस्ट सबमिशन केमिकल का प्रिक्योरमेंट करने का एक्शन प्लान। दूसरा, मैकेनिकल डोर स्वीपिंग का एक्शन प्लान। तीसरा, जो यह मशीनें धूल को खींचती हैं, उसके डिस्पोजल का एक्शन प्लान। चौथा, हमने इस बार सभी विभागों को विशेष कार्य दिया है कि हर विभाग जमीन पर काम करने वाले अपने जूनियर इंजीनियर, एई और ठेकेदारों संवेदनशील बनाने और उनके माइंड सेट को बदलने करने का काम करें।

दिल्ली को जल्द मिलेगा एक और मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

नई दिल्ली। कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश में जुटी हुई है. दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका में एक नया मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा.

द्वारका में तैयार किए जा रहे इस मल्टी स्टोरी अस्पताल भवन को कुल 24 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है. इस पर कुल लागत 932 करोड़ आने का अनुमान है. कोरोना की संभावित थर्ड वेव के चलते इसको और ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो द्वारका सब-सिटी में बन रहे इस अस्पताल का आसपास की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. सब-सिटी में बनाया जा रहा यह अस्पताल अपने आप में पहला सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल होगा.

बताया जाता है कि द्वारका सेक्टर-9 में लंबे समय से निर्माणाधीन इंदिरा गांधी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की इमारत को 30 जून को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया था. इस अस्पताल की इमारत भूकंपरोधी व दिव्यांगों के लिए अनुकूल है.

डीडीए ने 1997 में आवंटित की थी अस्पताल के लिए जमीन- बताते चलें कि अस्पताल के लिये जमीन का आवंटन 1997 में हुआ था. इसके लिये पूर्व की शीला दीक्षित की सरकार द्वारा 2007 में अस्पताल निर्माण के लिये 350 करोड़ रुपये का फंड भी आवंटित किया था. लेकिन करीब 24 साल से इस अस्पताल का निर्माण अधर में लटका हुआ था. अस्पताल की आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रखी थी.

हालांकि वर्ष 1997 में डीडीए ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित की थी. लेकिन अब यह 24 एकड़ में तैयार किया जा रहा है. 15 एकड़ में इसका निर्माण 750 बेड के रूप में किया जाना था लेकिन आबादी और जरूरत बढ़ने के हिसाब से इसको 24 एकड़ में 1241 बेड का कर दिया गया.

भविष्य में मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की भी योजना- स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस अस्पताल में एक हिस्से को खाली रखा गया है. इस एरिया में अस्पताल प्रशासन की ओर से भविष्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किए जाने की योजना है. इससे न केवल मेडिकल की सीटों में बढ़ोत्तरी हो सकेगी बल्कि क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज भी मिल सकेगा.

अस्पताल में मरीजों को मिलेंगी ये सभी खास मेडिकल सुविधाएं- नवनिर्मित अस्पताल में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, आर्थोपेडिक विभाग, मेडिसन विभाग, सर्जरी विभाग, नेत्र विज्ञान विभाग, ईएनटी (आंख- कान-गला) विभाग, त्वचा विभाग, पैथोलाजी विभाग, माइक्रो बॉयोलाजी विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, रेडियोलाजी विभाग व पीडिऐट्रिक्स विभाग शामिल है। साथ ही इसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, लैब सर्विस, रेडियोलाजी (एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड), ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी, आईसीयू व डायलिसिस आदि की सुविधा भी होगी. अस्पताल में डायलिसिस को सुवधिा भी मुहैया कराई जाएगी.

ऑक्सीजन प्लांट व स्टोरेज टैंक स्थापित किए जा रहे- इन सुविधाओं के अलावा अस्पताल प्रशासन की ओर से यहां पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाये जा रहे हैं. ऑक्सीजन स्टोरज की व्यवस्था के लिये यहां पर ऑक्सीजन टैंक भी लगाये जा रहे हैं. जसिसे कि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकेगी. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कल्लित के चलते सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन स्टोरेज और टैंकर आदि की व्यवस्था की जा रही है.

आसपास के अस्पतालों पर कम हो सकेगा मरीजों का दवाब- अस्पताल का निर्माण पूरा होने के बाद साउथ वेस्ट दिल्ली के जिन इलाकों को इससे बड़ा फायदा होगा उनमें द्वारका के अलावा पालम, पालम कालोनी, नजफगढ़, मधु विहार, राज नगर, उत्तम नगर, जनकपुरी आदि क्षेत्र के लाखों लोगों को इससे फायदा होगा.

मौजूदा समय में कोई बड़ा अस्पताल नहीं होने की वजह से हरि नगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पर भारी दवाब रहता था. हालांकि अभी जनकपुरी अस्पताल भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है. इन दोनों अस्पतालों पर मरीजों का दवाब बना रहता है. जानकारी के मुताबिक इन अस्पतालों के अलावा क्षेत्र के लोगों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग और दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये जाना होता था.

अब 1 अक्टूबर से दिल्ली में कभी नहीं खुलेंगी शराब की सभी प्राइवेट दुकानें

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू कर चुके आबकारी विभाग ने वर्तमान में चल रहीं शराब की सभी प्राइवेट दुकानों को सदा के लिए एक अक्टूबर से बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी एक अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें नहीं खुलेंगी।

इन दुकानों की संख्या अब 260 है। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की दुकानें खुलनी हैं। इसमें 32 जोन में से 20 जोन की नीलामी हो चुकी है। 12 जोन के लिए भी अगले कुछ दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी है। ऐसे में पुरानी दुकानों को धीरे धीरे बंद किया जाना है। इसलिए अभी प्राइवेट दुकानों को बंद किया जाएगा, इसके बाद 16 नवंबर से वर्तमान में चल रहीं सभी सरकारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी।

उधर, शराब दुकानदार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा है कि हम दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार से आग्रह करते हैं कि वह भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते हुए हमारे धंधे को ना उजाड़ें, अन्यथा इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली में एक अक्टूबर से शराब की दुकानों के बंद होने को लेकर शराब दुकानदार एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकता है, क्योंकि शराब की दुकानों को बंद होने में एक पखवाड़ा भर बचा है।

बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ने कुल 32 में से 20 जोन में शराब की खुदरा बिक्री के लिए निजी कंपनियों का चयन कर लिया है। दिल्ली आबकारी विभाग ने हालिया जारी एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत खुदरा लाइसेंस 17 नवंबर से जारी होंगे।

बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी से युवक घायल, आरोपित फरार

नई दिल्ली । उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक परिचित महिला के जन्मदिन में जाना एक शख्स को भारी पड़ गया। महिला के बुलावे पर उनके घर गए शख्स का अन्य लोगों से झगड़ा हो गया। आरोप है कि कुछ बिन बुलाए लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे युवक बुरी तरह से जख?मी हो गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीक के अस?पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पीड़ित के बयान पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

घायल की पहचान एम सिंह के रूप में हुई। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा है कि शुक्रवार रात आनंद विहार में वे बुलावे पर एक परिचित महिला के घर गए। वहां बर्थडे पार्टी थी। वहां महिला के अलावा उसके घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। पार्टी देर रात तक चली। रात करीब एक बजे तीन शख्स महिला के घर पहुंचे और उनके पति से कहासुनी करने लगे। फिर एक ने चाकू निकालकर उनके पति पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही उनको बचाने की कोशिश की तो आरोपितों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों की पहचान शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आरोपितों को आसानी से पकड़ा जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपितों को गिरफ्तार कर जल्द जेल भेजा जाएगा।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश, कहा- धार्मिक स्थलों को लेकर जल्द करें निर्णय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की सरकार को उस प्रतिवेदन पर फैसला लेने का निर्देश दिया जिसमें श्रद्धालुओं को कोविड-19 संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए धार्मिक स्थानों पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव' की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, ''हम संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारियों को मामले में लागू कानून, नियमों और सरकारी नीति के अनुसार 25 जुलाई 2021 के प्रतिवेदन पर फैसला करने का निर्देश देते हैं.''

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में ''अच्छी-खासी कमी'' को देखते हुए प्राधिकारियों ने मॉल, जिम और स्पा समेत कई स्थानों को खोलने की अनुमति दे दी लेकिन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 30 अगस्त के ताजा आदेश में भी धार्मिक स्थानों को नहीं खोला गया. उन्होंने कहा, ''धार्मिक स्थान खुल सकते हैं लेकिन आम जनता को आने की अनुमति नहीं हैÿमैंने श्रद्धालुओं को आने की अनुमति देने का प्रतिवेदन 40 दिन पहले भेजा था.'' दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा, ''हम उन्हें इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दे रहे हैं.''

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है

वकील रॉबिन राजू के जरिए दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि ''ऑनलाइन पूजा करने की सेवा देने से वैसा अनुभव नहीं मिल सकता जो'' जो शारीरिक रूप से जाकर दर्शन करने में मिलता है और श्रद्धालुओं पर जारी पाबंदी से ''ऐसा लगता है कि प्राधिकारी धार्मिक स्थलों को केवल पूजा स्थलों के तौर पर देखते हैं न कि जरूरत के तौर पर.''

साथ ही याचिका में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी और मनमाना है तथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

19 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली । अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इस रविवार (19 सितंबर) को कुमाऊं (उत्तराखंड) का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पिछले एक साल से काफी सक्रिय है। यहां पर बता देना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का एलान कर चुकी है।

पिछले दिनों उत्तराखंड दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से कर्नल (रिटायर्ड) अजय कोठियाल को बतौर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले दिनों मीडिया और लोगों की मौजूदगी में,क्कके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम की घोषणा की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा था कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे।

खूब तारीफ की थी कर्नल कोठियाल की

मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी का एलान करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कर्नल (रिटायर्ड) अजय कोठियाल की जमकर तारीफ की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कर्नल ने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। वह आज भी अपने शरीर में दो गोलियां लेकर घूमते हैं। जब उत्तराखंड के नेता इस प्रदेश को लूट रहे थे, तब यह शख्स सीमा पर देश की हिफाजत में लगा था। कुछ साल पहले केदारनाथ आपदा आई थी। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, अब इन्होंने उत्तराखंड के नवनिर्माण का बीड़ा उठाया है।

संपादकीय

तस्करी का सामान नहीं भावी पीढ़ी

सीमा (बदला हुआ नाम) को महज 13 साल की उम्र में उनके गांव के कुछ लोगों द्वारा चुराकर दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी में बेच दिया गया था। फिर प्लेसमेंट एजेंसी से एक दंपति ने उन्हें घरेलू कामगार के रूप में केवल 20,000 रुपये में खरीद लिया। लेकिन वहां से मजदूरी के नाम पर उनको एक रुपया भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, नियोक्ताओं और ट्रैफिकर (तस्कर) द्वारा उनका बार-बार बलात्कार और शोषण किया जाता रहा। अपनी बेटी के लापता होने से निराश और घनघोर पीड़ा झेलने के बाद सीमा के मजदूर पिता हमारे पास आए। हमने सीमा को दिल्ली के एक घर में ढूंढ़ लिया। लेकिन, हमारे लिए यह हैरानी की बात थी कि गुलामी और शोषण से आजाद होने के बाद भी वह दुखी थीं और हमारे सामने नहीं आ रही थीं। पिता से मिलने के बजाय वह रोते हुए दीवार के पीछे छिप गईं। बहुत कुरेदने पर उन्होंने रोते हुए कहा, 'मैं पिता को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं अब गंदी हो चुकी हूं। मैं खुद को मार डालना चाहती हूं।' यह सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया।

यह केवल सीमा की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के सबसे गरीब, पिछड़े और हाशिये पर रहने वाले हजारों बच्चों और लड़कियों की कहानी है। दुनिया का कोई भी देश जब तक अपनी बेटियों की खरीद-फरोख्त को चुपचाप सहते जा रहा है, तब तक वह खुद को सभ्य नहीं कह सकता। किसी राष्ट्र की संपत्ति, शक्ति या प्रगति का कोई मतलब नहीं है, यदि उसके बच्चों को मध्ययुग की दास प्रथा की तरह जानवरों से भी कम कीमत में खरीदा और बेचा जाता है! चार दशक पहले 1980 में जब हमने पंजाब के सरहिंद के एक ईंट भट्ठे से वर्षों से कैद वासल खान और उनकी मासूम साबो को बंधुआ मजदूरी व गुलामी से मुक्त कराकर अपना अभियान शुरू किया था, तभी हमें समझ में आ गया था कि बाल श्रम और ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) सहित तमाम सिविल सोसायटी समूहों ने मानव व्यापार के इस खतरे को समाप्त करने हेतु एक मजबूत कानून के लिए दशकों से अभियान चला रखा है। वर्ष 2017 में सीमा और उनके जैसे बाल दासता से मुक्त हजारों बच्चों और युवाओं ने इस कानून की मांग को लेकर देश के कोने-कोने में सरकारों, न्यायपालिका, धर्मगुरुओं, कॉरपोरेट घरानों, छात्रों और सिविल सोसायटी के लोगों के साथ 'भारत यात्रा' में कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। इस देशव्यापी यात्रा में 12 हजार किलोमीटर की दूरी तय की गई और 12 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। सबकी जुबान पर एक ही मांग थी कि भारत को बच्चों की खरीद-फरोख्त और शोषण रोकने के लिए एक व्यापक मानव तस्करी विरोधी कानून पारित करना चाहिए। 'भारत यात्रा' में शामिल बाल दासता और मानव व्यापार से मुक्त बहादुर नौजवानों के मन को छू लेने वाले गीत अब भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं- बिकने को तैयार नहीं हम, लुटने को तैयार नहीं हम।

केंद्र सरकार ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया है। इसे संसद को पारित करना है। बिल का उद्देश्य अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारणों, तस्करों को सजा, पीड़ितों की सुरक्षा व पुनर्वास सहित मानव व्यापार के सभी पहलुओं से निपटना है। यह एक व्यापक और मजबूत विधेयक है। कोविड-19 महामारी और इससे उपजी परिस्थितियों ने इस कानून की आवश्यकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और आर्थिक संकट के चलते देश के लाखों गरीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन न रहने का फायदा तस्कर उठा रहे हैं। बीबीए के आंकड़े बाल तस्करी बढ़ने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। संगठन ने पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक सरकारी एजेंसियों के सहयोग से 9,000 से भी ज्यादा बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त कराया है। इसकी तुलना में महामारी से पहले 14 महीने की समान अवधि के दौरान करीब 4,700 बच्चों को मुक्त कराया गया था। ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता का एहसास कराते हैं। इसीलिए यदि हमें महामारी के प्रभाव से उबरना है, तो इसके मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए तस्करी विरोधी कानून को फौरन पारित कराने के साथ ही हमें बच्चों के लिए सालाना बजटीय आवंटन में भी वृद्धि करनी होगी। मानव व्यापार अपने आप में एक संगठित अपराध है। लेकिन यह कई अन्य अपराधों को भी जन्म देता है। यह एक समानांतर काली कमाई वाली अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, जो बाल श्रम, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरन भिक्षावृत्ति, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य अवैध व्यवसायों को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता के अलावा तस्करी के अपराध को भी भारत के संविधान के तहत दंडनीय बनाया। लिहाजा, एक मजबूत 'एंटी ट्रैफिकिंग' कानून हमारे निर्वाचित नेताओं की नैतिक और सांविधानिक जिम्मेदारी है और राष्ट्र-निर्माण और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम भी। दरअसल, बच्चों की गरीबी, मजदूरी, अशिक्षा और सुरक्षा हमारी राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में नहीं रहे हैं। लेकिन, हमारे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि एक पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए इस मुद्दे को राजनीति और विकास के केंद्र में लाया जाए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाया जाए। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे भारत सरकार अमृतोत्सव के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भारतमाता के लिए उसके बच्चों की आजादी से बड़ा तोहफा भला और क्या हो सकता है? हमारे नीति-निर्माता बाल तस्करी के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाकर हमारे बच्चों को आजादी, सुरक्षा व गरिमा का अमृत प्रदान कर सकते हैं।

प्रवीण कुमार सिंह

एक साथ दो मोर्चों पर लड़ती हिंदी, राजकाज की भाषा के रूप में इसकी भूमिका सीमित

भारत की बहुभाषिकता को संवर्धित करते हुए हिंदी आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत सहित विश्वस्तर पर ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में विकसित हो सकती है।

हम दुनिया के तमाम देशों पर एक नजर दौड़ाएं तो उच्च स्थान पर वही राष्ट्र हैं जिन्होंने शिक्षा, व्यापार और सरकारी कामकाज, इन सबके बीच मातृभाषा को स्वीकारा और बढ़ावा दिया है। हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को स्वीकार करना, उन्हें शिक्षा, व्यापार और सरकार की भाषा बनाना ही वास्तव में भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाना है और सही अर्थो में हिंद स्वराज को साकार करना है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो स्वप्न भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, वह इसी तरह पूर्ण होगा।

हिंदी एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक ओर शिक्षा का मोर्चा है तो दूसरी तरफ बाजार। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा से निर्मित होने वाली अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, वहीं बाजार की दृष्टि से भी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, लेकिन बाजार जहां हिंदी और भारतीय भाषाओं में विस्तार पा रहा है, वहीं शिक्षा में भारतीय भाषाएं सिकुड़ती जा रही हैं। यह कमजोरी पहले केवल उच्च शिक्षा के संस्थानों में थी, जहां हिंदी और भारतीय भाषाओं को लगभग निषिद्ध घोषित कर दिया गया था, वहीं अब माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं उपेक्षणीय हो गई हैं। सामान्यजन के बदलते दृष्टिकोण के पीछे निश्चित रूप से शासकीय नीतियां और समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग की भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा एवं अंग्रेजी के प्रति अतिशय मोह बड़ा कारण रहा है।

आजादी के तत्काल बाद जिस जज्बे के साथ इस देश ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था और यह सपना देखा था कि हिंदी अगले 10- 20 वर्षो में समस्त भारत की संपर्क भाषा, राजभाषा और उससे आगे बढ़कर राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होगी, वह स्वप्न अब भी अधूरा है। सामान्यतः सिद्धांत है कि जो भाषा बाजार में चलती है वही अंततः राज और समाज की भाषा बनती है, लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ इसका उलटा हो रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में विशेषतः खुदरा व्यापार में हिंदी और भारतीय भाषाएं अपरिहार्य हैं, पर समाज के संचालन और राजकाज की भाषा के रूप में इनकी भूमिका अब भी सीमित है।

देश में अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या भारतीय संविधान की

आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा से कम है। बावजूद इसके वह अब भी पूरे भारत के राजकाज की भाषा बनी हुई है। इसी कारण यह एक वर्चस्वशाली भाषा है। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीय भाषाओं के बीच की समरसता और बहुभाषिकता की स्वीकृति के प्रति संदेह पैदा हुआ, जबकि भारत में भाषा संस्कृति के निर्माण, मनुष्य के बलिदान और स्वाभिमान तथा जीवन का साधन रही है। भारत में भाषा का लोकोत्तर चरित्र है। उसका परंपरागत इतिहास है।

उसे ज्ञान के विस्तार और ज्ञान की निर्मिति के लिए उपलब्ध साधन के रूप में देख सकते हैं। सभी भारतीय भाषाओं में ऐसी पूरकता है जिससे भारत नाम के सांस्कृतिक राष्ट्र की निर्मिति होती है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधता है। इसकी विविधताओं को स्वीकार करके राष्ट्रीय एकता सिद्ध होती है। हालांकि संसद की चर्चा का अधिकांश हिस्सा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में हुआ है, पर अभी भी कार्यपालिका में इनका प्रयोग सापेक्षिक रूप से कम है। न्यायपालिका में तो हिंदी एवं भारतीय भाषाएं प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उच्च शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस देश के भाषायी कुलीन श्रेष्ठ शिक्षकों एवं शोधवेत्ताओं ने पूरे प्रयास से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा एवं शोध की भाषा बनने से रोका है। तर्क यह है कि हमारी भाषा में सामग्री नहीं है। इस नाते हम अंग्रेजी में पढ़ने के लिए बाध्य हैं।

हम जानते हैं कि स्नातक में आने वाला हमारा विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को कितना समझ पाता है? भाषा सीखते-सीखते ही उसकी जिंदगी चली जाती है। इस संदर्भ में 'स्वराज इन आइडियाज' में केसी भट्टाचार्य लिखते हैं कि मैं इस स्थिति में आ गया हूं कि बांग्ला में कुछ भी नहीं सोच सकता। जो सोचता हूं, उसे बांग्ला में लिख नहीं सकता, इसलिए मेरे द्वारा लिखित 'स्वराज इन आइडियाज' में भी मौलिकता नहीं आएगी। भट्टाचार्य की स्वीकारोक्ति का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा पद्धति की स्थापना का प्रयत्न करना होगा जिसमें सृजनात्मक कल्पनाएं और नई संभावनाओं का चिंतन मनुष्य अपनी मातृभाषा में कर सके।

इसके लिए हमें दुनिया में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के संसाधनों, तकनीकी उपकरणों के संसाधनों, संप्रेषण के माध्यमों का समन्वित प्रयोग करते हुए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने का यत्न करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर ही इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में भारतीय भाषाओं में अध्यापन प्रारंभ होना एक युगांतकारी घटना है, जो सही संदर्भो में मैकाले को खारिज करते हुए भारत के लोगों के लिए भारत की जुबान में शिक्षा हो, इसका पथ प्रदर्शित करती है। शिक्षा के भारतीयकरण का अभियान भी भाषा के माध्यम से ही होगा। इसका सृजनात्मक पक्ष देखने को मिलने लगा है। हिंदी को लेकर जन स्वीकृति का जो स्वरूप बन रहा है, उसे शिक्षा में उतारना होगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति में चयन मूलक स्वतंत्रता और आवश्यकता मूलक चयन की दृष्टि से भारतीय भाषाओं को प्रस्तुत किया गया है। भारत की बहुभाषिकता को संवर्धित करते हुए हिंदी आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत सहित विश्वस्तर पर ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में विकसित हो सकती है।

हम दुनिया के तमाम देशों पर एक नजर दौड़ाएं तो उच्च स्थान पर वही राष्ट्र हैं जिन्होंने शिक्षा, व्यापार और सरकारी कामकाज, इन सबके बीच मातृभाषा को स्वीकारा और बढ़ावा दिया है। हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को स्वीकार करना, उन्हें शिक्षा, व्यापार और सरकार की भाषा बनाना ही वास्तव में भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाना है और सही अर्थो में हिंद स्वराज को साकार करना है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो स्वप्न भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, वह इसी तरह पूर्ण होगा।

ट्राइब्यूनल पर टकराव

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्राइब्यूनल में खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी को लेकर असाधारण सख्ती दिखाई है। उसने कहा है कि लगता है जैसे सरकार के मन में इस कोर्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर नियुक्तियां करने को कहा। अदालत को हैरानी इस बात पर थी कि बार-बार कहने और मौजूदा कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। सरकार की ओर से इसका कोई ढंग का स्पष्टीकरण भी पेश नहीं किया जा सका कि आखिर नियुक्तियां न किए जाने की क्या वजह रही। लेकिन मामला सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं

अदालत की नाराजगी सरकार की ओर से पिछले महीने लाए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर भी है। इससे मिलते-जुलते प्रावधानों वाले पिछले कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। इसके बावजूद वैसे ही प्रावधान नए कानून की शक्ल में लाए गए। शीर्ष अदालत ने इस पर तीखी आपत्ति करते हुए कहा कि हम किसी कानून के खिलाफ फैसला देते हैं, आप कुछ दिनों बाद वैसा ही नया कानून ले आते हैं। यह एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे ऐसा संदेश जा सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं करती।

अदालत ने जिम्मेदारी और अधिकारों की बारीक सीमा को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार फैसले का मुख्य संदेश ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप नया कानून बना सकती है, वह किसी फैसले के आधार को भी बदल सकती है, लेकिन फैसले की मुखालफत करते हुए कोई नया कानून नहीं बना सकती। फैसले का आधार बदलने और मुखालफत करने के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए अंतर पर थोड़ा गौर किया जाए तो साफ होता है कि सरकार किसी खास कानून में संशोधन करके कोर्ट द्वारा की गई उसकी पिछली व्याख्या के आधार को और विस्तृत कर सकती है, जिससे हो सकता है अगली बार कानून की वह व्याख्या बदल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के जिस प्रावधान को खारिज करे, वही प्रावधान फिर से लाए जाएं तो यह कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो जाता है। इसे ठीक नहीं माना जा सकता।

वैसे यह भी सच है कि अभी इस मामले की सुनवाई चल ही रही है और केंद्र सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जाना बाकी है। अभी यह मानना मुनासिब होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गंभीरता को समझती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में उसके आदेशों की अनदेखी हुई है तो सरकार को इस मामले की तह तक जाते हुए उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अविलंब दूर करना चाहिए।

चीन-पाक साठगांठ से निपटने और अफगान में अपने हितों के लिए निकालना होगा तोड़

करीब- दो दशक के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान फिर से काबिज हो गया है। यह वही कट्टरवादी ताकत है जिसने अपने पिछले दौर में ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, भारतीय विमान अपहरणकर्ताओं का मध्यस्थ बना और बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ीं। तालिबान ने जिस रफ्तार से काबुल पर कब्जा जमाया और अपनी ताकत को दिखाया, उसका अनुमान किसी को नहीं था। अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह एक बहुत बड़ी घटना है, जो भारत के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस घटना के बाद दुनिया में शांति प्रहरी के रूप में अमेरिका की छवि में भारी गिरावट आई है। अफगानिस्तान में दो दशक तक चली लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने करीब 70,000 सैनिक गंवाए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इस लड़ाई पर लगभग दो लाख करोड़ डालर खर्च किए। फिर भी युद्ध के अंत में अमेरिका एक भी सफलता नहीं गिना सकता। हां, उसने लादेन को जरूर मार गिराया, लेकिन वह भी अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में। इस बीच अमेरिका के खिलाफ नफरत से भरा कट्टरवाद लगातार नए ठिकाने ढूंढ रहा है।

यह मान लेना एक भूल होगी कि तालिबान की ताकत अब सीमित रहेगी। उसने उस अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, जहां अमेरिकी समर्थन से दो दशकों तक सरकार चली। वहां अब पहले से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्टर है। अमेरिकी हथियारों समेत आधुनिक सैन्य बल है, जो सीधे तालिबान की झोली में आ गया है। संभव है अब अमेरिका और पश्चिमी देश वहां से दूर ही रहेंगे, जिसके कारण तालिबानी तौर-तरीकों का रास्ता रोकने वाली कोई भी सैन्य शक्ति नहीं रहेगी। वर्ष 2022 और उसके बाद इस बात की आशंका है कि तालिबान अन्य आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और पैसा देकर इजरायल और भारत के राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करेगा। आशंका है कि तालिबान के कट्टर समर्थक पाकिस्तान और कई अन्य पक्ष तमाम संवेदनशील मुद्दों को लेकर हावी हो जाएंगे। इनमें फलस्तीन भी शामिल है। अब वह उस खलीफा की स्थापना करने का प्रयास करेगा, जिसकी कोशिश आइएस ने की थी। आइएस के पास लंबी लड़ाई के लिए संसाधन नहीं थे, जबकि तालिबान के पास तीन करोड़ लोगों का अपना साम्राज्य है।

वर्ष 1996 में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया तभी से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी सरकार उसे पैसा मुहैया कराने के साथ ही बढ़ावा भी दे रहे थे। अब दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए चिंता इस बात को लेकर और बढ़ गई है कि अफगानिस्तान में नया तालिबानी शासन चीन की आर्थिक कठपुतली बनने की राह पर है। अगस्त के आरंभ में ही चीन ने स्पष्ट कर दिया था कि वह तालिबान को अफगानिस्तान के वैध शासक की मान्यता दे देगा। हाल में उसने बड़ी तेजी से अफगानिस्तान को लेकर अपनी आर्थिक दिलचस्पी बढ़ा दी है। चीन उस वखान कारिडोर की सड़क को पूरा करने में लगा है, जहां जमीन की एक पतली सी पट्टी चीन-अफगानिस्तान को जोड़ती है। चीन की नजर में अफगानिस्तान वह देश है, जिससे खनिज निकाल कर वह अपने उद्योगों को तेजी से दौड़ा सकता है। पूरे एशिया को जोड़ने वाला उसका महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान से गुजरता है। पाकिस्तान के साथ ही नया तालिबान निश्चित तौर पर हमारे चारों ओर की गई चीनी घेराबंदी का हिस्सा बन जाएगा और फिर चीन उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा।

ऐसे में भारत को बड़ी सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। हमें तालिबान के साथ कूटनीतिक माध्यम को बिना समय गंवाए मजबूत करना होगा। माना कि वह भारत का विरोधी है, लेकिन अभी उसके साथ बातचीत और कूटनीति संबंध रखने में ही बुद्धिमानी है। अगर हम अतीत को देखें तो पाएंगे कि तालिबान अराजक और अनुशासनहीन आतंकी संगठन रहा है, जिसके भीतर ही कई खेमे हैं। अब तक वे एकजुट थे, क्योंकि उन सभी का दुश्मन अमेरिका था, पर अब वह जा चुका है। लिहाजा तालिबानी मुजाहिदीनों में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच टकराव होना निश्चित है। भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी कलह का लाभ उठाने के लिए हमारा काबुल में मौजूद रहना जरूरी है। अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं में हमने अब तक 22,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमने अफगानियों के लिए कारोबार और तकनीकी सहयोग के रास्ते खोले हैं। हमें संपर्क के इन माध्यमों को बनाए रखना होगा। नए तालिबान को नया आर्थिक साझीदार बनाने का प्रयास करना होगा। हमें इस घटना से उत्पन्न व्यापक भू-राजनीतिक परिस्थिति पर भी नजर रखनी होगी। अमेरिका अब इराक और अफगानिस्तान से जा चुका है, जबकि पाकिस्तान चीन के खेमे में चला गया है। अमेरिका को एशिया में एक मजबूत लोकतांत्रिक सहयोगी की जरूरत होगी। भारत ही उस कमी को पूरा कर सकता है।

महबूबा मुफ्ती का कश्मीर के तालिबानीकरण का मंसूबा कभी नहीं हो पाएगा कामयाब

अन्यथा अनुच्छेद 370 के बाद आतंक की कमर तोड़ने का जो रणनीतिक लाभ हासिल हुआ था वह जाता रहेगा। साथ ही राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को जल्द संपन्न कर विधानसभा चुनाव कराने चाहिए। फिर पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की दिशा में कदम उठाए जाएं। इससे न केवल कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय दुष्प्रचार पर प्रहार होगा, बल्कि जनादेश के आधार पर गठित लोकतांत्रिक सरकार के सत्तारूढ़ होने से तालिबानी मानसिकता को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जम्मू-कश्मीर की जनता अब शांति के साथ समृद्धि चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उनकी गति और तेज की जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है, लेकिन हाल में उन्होंने दुस्साहस की सभी सीमाएं तोड़ दीं। अफगानिस्तान में तालिबान के हालिया कब्जे की मिसाल देते हुए उन्होंने भारत सरकार को खुली धमकी दी कि वह कश्मीरियों के सब्र का और इम्तिहान न ले और अमेरिका से सबक सीखे कि उसे कैसे अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर भागना पड़ा। उनके बयान से प्रतीत होता है कि वह स्वयं को तालिबान और भारत को अमेरिका मान रही हैं। ऐसे मुगालते के साथ वह यह भूल रही हैं कि कश्मीर अफगानिस्तान की तरह कोई आजाद मुल्क नहीं, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। इससे दुनिया को दिखा होगा कि कश्मीर की स्वयंभू लोकतंत्रवादी और मानवाधिकारवादी दरअसल तालिबान की हिमायती और हमदर्द हैं। महबूबा चाहें तो अपनी अलगाववादी ढपली पर तालिबानी राग गाएं, लेकिन कश्मीर के तालिबानीकरण का उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। इस बयान ने उनकी तालिबानी मानसिकता का ही परिचय दिया है। उनके बयान पहले भी अलगाववाद की आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन एक महिला होने के बावजूद तालिबान की वकालत करने वाली महबूबा क्या यह चाहती हैं कि कश्मीर में भी बहन-बेटियों के पढ़ने-लिखने और कामकाज पर पाबंदी लग जाए। तालिबान द्वारा महिलाओं को 'यौन दासी' बनाने जैसी कुप्रथा पर उनका क्या मत है? क्या वह चाहती हैं कि सवालों के जवाब जुबान के बजाय गोलियों से मिलने लगें।

तालिबान की असलियत जगजाहिर है। वह मध्यकालीन मानसिकता वाला महिला और लोकतंत्र विरोधी क्रूर आतंकी संगठन है। कश्मीर में उसकी आमद की कामना करना महबूबा के वास्तविक मंसूबों और बिगड़ते मानसिक संतुलन को उजागर करता है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को धमकाने के फेर में वह संभल से सपा के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क और शायर मुनव्वर राना से भी दो कदम आगे निकल गई हैं। वह यह भी भूल गई कि सत्ता की जिस भूख और भाजपा से नफरत ने उनके विवेक पर आघात किया है उसी के साथ वह और उनके पिता गठबंधन सरकार चला चुके हैं। क्या इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए वह भाजपा, कांग्रेस और यहां तक कि तालिबान का भी सहारा ले सकती हैं। अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेंस के साथ गुपकार गठजोड़ बनाना भी उनके सत्तालोलुप चरित्र और अवसरवाद की एक और नायाब मिसाल है।

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की मिसाल के माध्यम से उन्होंने एक तरह से कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों के हमदर्द होने और उनके तार तालिबान से जुड़े होने का भी सुबूत दिया है। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोइबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देकर वहां की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कराने में अपनी भूमिका निभाई है। उसी से उत्साहित होकर उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी देने की हिमाकत की है। उल्लेखनीय है कि जेल में बंद पीडीपी के तथाकथित युवा नेता वहीद-उर-रहमान परा के आतंकी जुड़ाव की पुष्टि हो चुकी है। फिर भी पीडीपी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तालिबान की धमकी देना पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जयचंद द्वारा मुहम्मद गोरी को दिए गए न्योते की याद दिलाता है। महबूबा को खुद तय करना है कि क्या वह भारतीय इतिहास में एक और जयचंद के रूप में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। यह अलग बात है कि 21वीं सदी के संगठित और सशक्त भारत में मुहम्मद गोरी अर्थात तालिबान का हश्र बहुत भयानक होगा।

केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती द्वारा लगातार दिए जा रहे भड़काऊ बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। नजरबंदी से निकलने के बाद वह एक के बाद एक ऐसे बयान देकर राष्ट्रविरोधी विमर्श को हवा दे रही हैं। पत्थर और बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए कश्मीरी युवाओं को वह फिर भड़काने की फिराक में हैं। दरअसल हिंसा, आतंक और अलगाववाद उनकी राजनीति का आधार रहा है। वह किसी भी कीमत पर उसके परित्याग को तैयार नहीं दिख रहीं। उनके ऐसे रवैये से आतंकियों एवं बिगड़ैल पड़ोसी के हौसले और बढ़ते हैं। इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई जरूरी हो गई है। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि कश्मीर के मसलों का समाधान पड़ोसी देशों और भाड़े के आतंकियों के हमदर्द और हिमायती बनने से नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक प्रक्रियाओं में आस्था रखने और उनका सम्मान करने से निकलेगा।

जहां तक पाकिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने से उसकी बांछें खिली हुई हैं। आइएसआइ को कश्मीर अंतिम सांसें गिन रही आतंकी जड़ों में नई जान आने की उम्मीद बंधी है। इसीलिए भारत सरकार बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और चाकचौबंद करे। अन्यथा अनुच्छेद 370 के बाद आतंक की कमर तोड़ने का जो रणनीतिक लाभ हासिल हुआ था वह जाता रहेगा। साथ ही राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को जल्द संपन्न कर विधानसभा चुनाव कराने चाहिए। फिर पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की दिशा में कदम उठाए जाएं। इससे न केवल कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय दुष्प्रचार पर प्रहार होगा, बल्कि जनादेश के आधार पर गठित लोकतांत्रिक सरकार के सत्तारूढ़ होने से तालिबानी मानसिकता को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जम्मू-कश्मीर की जनता अब शांति के साथ समृद्धि चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उनकी गति और तेज की जानी चाहिए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

शराब पीने का विरोध करती थी पत्नी, पति ने रच डाली खौफनाक मौत की ये साजिश

आरा । भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र के जेठवार गांव में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई।घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है।जानकारी के अनुसार मृतिका 35 वर्षीया पत्नी पिंकी देवी जेठवार गांव निवासी सुनील राम की पत्नी थी । पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इधर मृतिका के बहन के बेटे जय अमर कुमार ने बताया कि उसका पति बराबर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे उसके मौसी के ससुराल वालों ने फोन किया कि तुम्हारी मौसी की मृत्यु हो गई है।

पति को पुलिस ने किया अरेस्ट- सूचना पाकर मृतिका के परिजन ने इसकी सूचना फौरन स्थानीय थाना को दी।इसके बाद मृतिका के परिजन थाना पहुंचे। जिसके बाद थाने की पुलिस के साथ परिजन उसके ससुराल पहुंचे।जहां उन्होंने देखा कि कर दी गई।घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है।जानकारी के अनुसार मृतिका 35 वर्षीया पत्नी मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी है।जिसके पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया।वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतिका के पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मृतिका के बहन के बेटे जयराम कुमार ने उसके पति,देवर एवं गोतनी पर जमीन के विवाद को लेकर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। इधर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सह प्रभारी अधीक्षक डा.एल.पी.झा के निर्देश पर तीन सदस्य डाक्टर की टीम गठित कर शव का पोस्टमार्टम किया गया। गठित तीन सदस्य बोर्ड में आन ड्यूटी चिकित्सक डा.शैलेंद्र कुमार, डा.प्रभात प्रकाश एवं डा.विकाश सिंह शामिल थे।

झारखंड पुलिस के 6800 जवानों की जा सकती है नौकरी

रांची । झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6800 जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाई कोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेजकर बताया है कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी कहना है कि तो वे जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं, ताकि ससमय हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने जवानों को यह नोटिस सभी जिलों के एसएसपी-एसपी, इकाई प्रमुख के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के माध्यम से जारी किया है। सिपाही बहाली के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन संख्या 04/2015 निकला था, जिसके तहत वर्ष 2017 में 6800 जवान बहाल किए गए थे। इस बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति नियमावली को चुनौती देकर वर्ष 2017 में हाई कोर्ट में एक याचिका सुनील टुडू बनाम झारखंड राज्य व अन्य दायर किया गया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2021 को है। गत 23 अगस्त को ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस याचिका में अदालत का जो अंतिम निर्णय होगा, उससे यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को इससे अवगत कराया था, जिसके बाद ही पुलिस मुख्यालय से एडीजी मुख्यालय ने सभी जिला व इकाइयों को उक्त नोटिस से अवगत कराया है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने वर्ष 2017 में बहाल सभी जवानों को धैर्य रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन खड़ा है। उन्होंने ऐसे सभी जवानों से अपने शाखा के माध्यम से पुलिस मेंस एसोसिएशन कार्यालय को अपनी सूची भेजने को कहा है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन सबसे सुझाव लेने के बाद संघ की ओर से अदालत में सूचना आवेदन देगा और आग्रह करेगा कि सुनील टुडू बनाम झारखंड सरकार व अन्य वाली याचिका को खारिज की जाय। उनके जवानों ने चार साल तक अपनी सेवा दे दी है, अब वे कहां जाएंगे। एसोसिएशन अदालत को बताएगा कि नियुक्ति में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी सभी जवाबदेही सरकार व प्राधिकार तथा नियुक्ति समिति के पदाधिकारियों की होगी। पीड़ित जवान किसी के बहकावे या भ्रम में न पड़ें और किसी तरह के चंदे एवं जल्दबाजी में कोई उगाही न करें।

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से शिक्षकों में उबाल, काला बिल्ला लगाकर जता रहे विरोध

पोटका (पूर्वी सिंहभूम) । निजी स्कूल न होते तो झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाता। इस तरह के बयान झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा दिए जाने के बाद सरकारी शिक्षकों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को कई सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से माफी मांगने मांगने की बात कर रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ।

झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव निखिल चंद्र मंडल का कहना है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का इस तरह का बयान देना अमर्यादित हैं। उन्होंने बयान को शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने वाला बताया है। इनका कहना है कि इस तरह सरकारी शिक्षकों को अपमानित करना गलत है। झारखंड सरकार को इस संबंध में प्रत्येक जिले से प्रखंड से निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के नाम भेजा जाएगा तथा रामेश्वर उरांव को इस तरह के बयान मीडिया में देने पर उन्हें सरकारी शिक्षकों से माफी मांगनी होगी। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष श्यामल कुमार मंडल ने कहा कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ वित्त मंत्री के बयान की घोर भर्त्सना करता है।

अमर दुबे की पत्नी के सामने चुप खड़े रहे वादी इंस्पेटर, नहीं मिला सके नजरें

कानपुर देहात । बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी की फर्जी दस्तावेज लगा सिम लेने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड में पेशी हुई तो सामने पड़े वादी इंस्पेक्टर चुप खड़े रहे। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने जब वादी इंस्पेक्टर से मामले में प्रश्न पूछने शुरू किए तो वह अपने ही जवाबों में उलझते रहे। गोलमोल जवाब देकर अपनी बात की पुष्टि करते नजर आए। नाबालिग के नाम सिम कैसे जारी होने और बालिग जैसा व्यवहार करने के प्रश्न पर जवाब नहीं दे सके। आरोपित व विवेचक के बयान दर्ज कर किशोर न्याय बोर्ड ने सुनवाई के लिए आगामी तिथि 23 सितंबर नियत की है।

चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। घटना सुर्खियों में आने के बाद सक्रिय हुई एसटीएफ और पुलिस टीम ने विकास दुबे समेत गैंग के सात अपराधियों को एनकाउंटर में मार दिया था। इसमें विकास दुबे के खास गुर्गा अमर दुबे भी हमीरपुर में एनकाउंटर में मारा गया था। घटना के तीन दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और चौबेपुर थाना पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया था। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज से मोबाइल सिम लेने का भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय वादी हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे नाबालिग घोषित किए जाने पर बाराबंकी राजकीय संप्रेक्षण गृह भेजा गया था और मामला किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था। अमर दुबे की पत्नी की सुनवाई अब किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है और सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड में उसकी और वादी की पेशी हुई और बयान दर्ज किए गए।

अमर दुबे की पत्नी को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होने व पत्रावली में एसआईटी रिपोर्ट न होने की दलील दी। वहीं विवेचक कृष्ण मोहन राय से आरोपित के नाबालिग होने के बाद भी बालिग जैसा व्यवहार करने का कारण पूछा, जिस पर वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। कोर्ट में मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सवाल पूछे जाने के दौरान आरोपित अमर दुबे की पत्नी से वादी इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय नजरें नहीं मिला सके और शांत खड़े रहे। दरअसल, इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय ने ही अमर दुबे की पत्नी को गिरफ्तार करके मुकदम दर्ज किया था। करीब दो घंटे चली बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क दिए गए और विवेचक से सवाल किए गए, जिस पर वह अधिकांश प्रश्नों के जवाब नहीं दे सके। बोर्ड ने बचावपक्ष व चौबेपुर थाने के विवेचक कृष्ण मोहन राय का बयान दर्ज किया। बचावपक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि न्यायालय में विवेचक व आरोपित के बयान दर्ज किए गए हैं और सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि नियतकी गई है।

दरभंगा में अधेड़ आशकि का खेल, छह माह बाद खुला राज, जानिए पूरा माजरा

दरभंगा । एक तरफा प्यार में एक 50 वर्षीय आशिक ने अपनी दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। घटना बिहार के दरभंगा की है। यहां एक नाबालिग लड़की से प्रतिदिन छेड़खानी करता था। यह आशिक स्वजनों के नाक में दम कर रखा था। मामला पुलिस में जाने के छह माह बाद पर्दाफाश हुआ। बताते चलें कि महिला थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करनेवाले अधेड़ को उसके पुत्र के साथ नगर थाने के सेनापत मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया। मो. शाहनवाज उर्फ गुलाब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि उसके नाबालिग पुत्र को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि पीड़िता की मां ने नौ मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 50 वर्षीय मो. शाहनवाज उर्फ गुलाब लड़की को कोड्क्षचग जाने के दौरान घेरकर बार-बार अश्लील हरकत कर रहा था। वह प्यार करने और शादी करने की बात करता था। इस बीच शहनवाज अपने दो साथियों के साथ पीड़िता के घर कार से पहुंचा। पीड़िता अपने घर के बाहर खड़ी थी। शाहनवाज नाबालिग का हाथ पकड़कर छेडख़ानी करने लगा। शोर करने पर कार में सवार दो अज्ञात फरार हो गए, लेकिन लोगों की मदद से आरोपित को पकड़ लिया गया। इसके बाद भीड़ में शमिल लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस सूचना पर आरोपित का नाबालिग पुत्र हथियार लेकर पहुंचा और अपने पिता को जबरन छुड़ाकर ले गया।

बिजनौर में दुष्कर्म का विरोध करने पर खिलाड़ी का किया था मर्डर, आरोपित गिरफ्तार

बिजनौर। बिजनौर में राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत के मामले में पुलिस ने राजफाश कर दिया है। दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर नेशनल खिलाड़ी की हत्या की गई थी। आरोपित को गिरफ्तार कर खून के धब्बे वाली शर्ट, रस्सी, आरोपित की चप्पल और शर्ट का टूटे बटन बरामद हुए हैं। मोबाइल बरामद कर लिए आरोपित को रिमांड पर लिया जा रहा है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस तेजी के साथ अपनी तफ्तीश की थी। कई लोगों से मर्डर के संबंध में पूछताछ की गई थी और वरिष्ठ अफसरों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था।

एसपी ने पीसी में यह बताया- बीते शुक्रवार को शहर की सर्वोदय कॉलोनी निवासी नेशनल खिलाड़ी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता में एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने बताया कि हत्याकांड में शामिल आरोपित शहजाद उर्फ खादिम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित रेलवे स्टेशन पर काम करता है और नशे का आदी है। आरोपित ने घटना के दिन स्लीपर के बीच जा रही युवती को गलत इरादे से पकड़ लिया था।

आरोपित की चप्पल भी मिली थी-

विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी थी। जांच में आरोपित की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। गायब युवती का मोबाइल आरोपित के घर पर बंद हुआ है। शहजाद की खून के धब्बे लगी शर्ट और दो टूटे बटन मिले हैं। बटन घटनास्थल से बरामद हुए थे। मृतका के हाथा-पाई के दौरान चेहरे, गर्दन और सीने पर नाखून के निशान भी मिले हैं। आरोपित की एक चप्पल भी बरामद हुई है, जो घटना के समय छूट गई थी। आरोपित की मुकदमे में दुष्कर्म के प्रयास की धारा बढ़ा दी गई है। आरोपित का चालान कर दिया गया है।

मोबाइल की बरामदगी के लिया लिया जाएगा रिमांड- एसपी ने बताया कि मोबाइल बरामद करना शेष है। इसके लिए आरोपित को कोर्ट से रिमांड लिया जाएगा। जल्द ही मोबाइल बरामद कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रयास शुरु कर दिए गए हैं।

अलीगढ़ के राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को अखिलेश यादव ने बताया भाजपा का ढोंग

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अलीगढ़ में जिस राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा का ढोंग बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर तंज किया है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की बदलती विचारधारा पर भी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजीवन साम्प्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे व भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है। अचानक भाजपा का यह कदम समझ से परे है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में मथुरा के वृंदावन में स्थापित गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन को भाजपा सरकार ने नकली विश्वविद्यालय घोषित करके उनका अपमान किया है। यह तो उनका पुराना फलसफा है कि भाजपा का सारा काम अच्छा और अन्य का सारा अच्छा काम भी बेकार।

लखनऊ की थप्पड़ गर्ल के बाद लात-घूसों वाला युवक, युवती को जमकर पीटा; लड़की पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप

लखनऊ । बीते अगस्त माह में बाराबिरवा चौराहे पर कैब चालक की युवती द्वारा थप्पड़ से पिटाई। पालीटेक्निक चौराहे के पास टेंपो चालक की महिला द्वारा चप्पल से पिटाई की घटना शहर वाले भूल नहीं पाए थे कि चारबाग में एक युवती की थप्पड़ और घूसों से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक चारबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे युवती को थप्पड़, घूसों और लातों से पीट रहा है। वहीं, भीड़ तमाशबीन खड़ी मोबाइल से वीडियो बनाती रही। युवती मदद की गुहार भी करती रही और युवक उसे पीटता रहा। वीडियो वायरल होते ही नाका पुलिस हरकत में आयी और आरोपित युवक को धर दबोचा।

दो पुलिस चौकियों के बीच, अरे भइया कोई बचा लो की गुहार करती रही युवती- वायरल वीडियो में युवक की थप्पड़ और घूसों से युवती को पीट रहा था। युवती लोगों से मदद की गुहार कर रही है कि अरे भइया कोई बचा लो। आस पास महिलाएं, पुरुष, मेट्रो के गार्ड और अन्य लोग

खड़े हैं। कुछ वीडियो बना रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी है, कुछ लोग विरोध करते दिखे पर हमलावर युवक के चंगुल से कोई भी युवती को छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा सका।

इस बीच एक युवक पीली शर्ट पहने पहुंचा और उसने विरोध कर युवती को छुड़ाया। इसके बाद आरोपित युवक गाली-गलौज करता हुआ चला गया। बता दें घटनास्थल नत्था और लोको पुलिस चौकी के बीच है। वहीं, चारबाग चौराहे पर भी पुलिस कर्मी हर समय ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसके बाद भी किसी को भनक नहीं लगी।

युवती ने की छेड़छाड़, अभद्र कमेंट इस लिए पीटा- इंस्पेक्टर नाका मनोज मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो में घटना सोमवार शाम की है। वीडियो के आधार पर आरोपित युवक की तलाश में दबिश दी गई। उसे पान दरीबा से पकड़ लिया गया। पकड़ा गया युवक पानदरीबा निवासी उज्जवल हांडा है।

उसने पूछताछ में बताया कि वह मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रहा था। इस बीच युवती मुंह पर दुपट्टा बांधे खड़ी थी। उसने देखते ही अभद्र कमेंट किए। विरोध पर गाली-गलौज की इस लिए उसे पीटा। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित उज्जवल को हिरासत में ले लिया गया है। युवती की तलाश की जा रही है। युवती अगर तहरीर देगी तो आरोपित के खिलाफ उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। नहीं तो शांति भंग की धारा में कार्यवाही पुलिस करेगी।

लखनऊ में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, होमगार्ड व ड्राइवर घायल; डंपर छुड़ा ले गए हमलावर

लखनऊ । अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची टीम पर मोहनलालगंज में माफिया ने हमला बोल दिया। हमलावर मिट्टी लदी डंपर भी जबरन छुड़ा ले गए। हमले में खनन निरीक्षक के ड्राइवर और एक होमगार्ड को चोट आई है। खनन निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत अज्ञात लोगों पर एफआइआर दर्ज की है। खनन अधिकारी दिनेश कुमार के मुताबिक रविवार रात करीब साढे दस बजे उन्हें सिसेंड़ी व सुल्सामऊ हिल्गी में अवैध खनन की शिकायत मिली। इसपर वह ड्राइवर राजकुमार शुक्ला, होमगार्ड रामसेवक, रामदास व राजकुमार के साथ जांच करने पहुंचे।

वहां भागूखेड़ा में एक डंपर मिला, जिसका नंबर प्लेट मिटा था और उसमें मिट्टी लदी हुई थी। डंपर चालक से जब मिट्टी के परिवहन के कागज मांगे गए तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इस पर खनन निरीक्षक ने दो होमगार्ड को ड्राइवर समेत डंपर को थाने ले जाने के निर्देश दिए। आरोप है कि तभी वहां काली रंग की एक स्कार्पियो व कार से कुछ लोग पहुंच गए। आरोपितों ने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद लाठी डंडे से हमला बोल दिया। यही नहीं डंपर भी वहां से लेकर चले गए। हमले में खनन निरीक्षक का ड्राइवर और एक होमगार्ड घायल हो गए।

आरोप है कि हमलावरों में सरोजनीनगर के संतोष यादव, अभिषेक यादव और उत्तरगांव के कमल किशोर समेत अन्य शामिल थे। पुलिस ने खनन अधिकारी दिनेश कुमार की तहरीर पर तीनों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने के प्रयास व सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओ में एफआइआर दर्ज की है। इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र का कहना है कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। खनन माफिया हावी - मोहनलालगंज में खनन माफियाओं का बोलबाला है। रात होते ही खनन के डंपर दौड़ने लगते हैं। रायल्टी के नाम पर मिट्टी का भी खेल खेला जाता है। सिसेंड़ी क्षेत्र में खनन माफिया हर रोज मिट्टी खनन करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।

बिहार में निशाने पर आए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, भोजपुरी और मगही बोलने वालों पर दिया था बयान

पटना । भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में सहयोगी दल राजद के प्रवक्ता ने उनके बयान का बचाव किया है। आपको बता दें कि हेमंत ने भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को डोमिनेटिंग नेचर यानी वर्चस्व चाहने वाला बताया है। हेमंत ने कहा कि अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले ये भाषाएं बोलते थे। झारखंड के आंदोलन के वक्त भोजपुरी में गालियां दी जाती थीं। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है और ये बिहार की भाषाएं हैं।

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने उनके बयान को बिहार का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि जदयू ने कभी जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में तो कोई फर्क ही नहीं है। भोजपुरी और मगही का साहित्य तो काफी समृद्ध रहा है।

झारखंड के सीएम की ओछी राजनीति- बीजेपी- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा संजय जायसवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भोजपुरी और मगही भाषा का हेमंत पर अपमान करने व हिंदी दिवस पर भाषा का अपमान करने को लेकर चिंता जताई है।

हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हेमंत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनसे ऐसे ही बयान की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उन्हें भोजपुरी और मगही के योगदान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।

राजद ने किया हेमंत सोरेन का बचाव

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मसले पर हेमंत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही होंगी। उन्होंने कहा कि भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और भोजपुरी एवं मगही का महत्व तो पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने इन भाषाओं के प्रति कोई विद्वेष नहीं दिखाया है।

नवादा जेल में पिटाई से हुई थी कैदी की मौत, जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा; जेलर पर लटकी तलवार

नवादा। मंडलकारा के बंदी गुड्डू कुमार की मौत में जांच पूरी कर ली गई है। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी यश पाल मीणा को सौंप दी है। जिसमें जेल के अंदर से बंदी की मौत सामने आई है और इसमें जेल प्रशासन की संलिप्तता है। अब इस रिपोर्ट के बाद जेल अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। टीम के अधिकारियों ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी की सीडी भी दी गई है। गवाहों का बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुल 70 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पीलिन रैप्चर्ड की बात सामने आई है। इससे साफ है कि जेल के अंदर निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई है। जिससे उसकी मौत हुई है।

चौंकाने वाली है जांच रिपोर्ट, घटना के दिन की फुटेज गायब

अधिकारियों की जांच में जेल प्रशासन की कलई खुल गई है। टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, वह काफी चौंकाने वाली है। जिलाधिकारी यश पाल मीणा ने बताया कि 6 सितंबर को गुड्डू की मौत को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच कराई गई थी। टीम में सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती, एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद, एसीएमओ डॉ. अखिलेश कुमार मोहन व डीआइयू के राजीव कुमार शामिल किया गया था। जांच टीम ने मंडल कारा पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि 5 सितंबर को 11.50 बजे के बाद कोई फुटेज नहीं है। ऐसे में साफ है कि जेल अधिकारियों ने राज उजागर होने के भय से सीसीटीवी को खराब कर दिया।

बंदियों के बयान भी अलग-अलग, पैदा कर रहे सवाल

जांच टीम ने मंडल कारा में बंद 70-75 बंदियों से अलग-अलग बयान लिया है। जिसमें उन बंदियों ने जांच अधिकारियों को अलग-अलग जानकारी दी है। किसी बंदी ने कहा है कि तबीयत बिगडने़ पर वार्ड के भीतर ही गुड्डू का इलाज किया गया तो किसी ने बताया कि वार्ड के बाहर। किसी ने सेल में इलाज करने की बात कही तो किसी ने जेल अस्पताल में।

नीतीश सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की बड़ी घोषणा, गया में लगेगी सीमेंट और सोलर इंडस्ट्री

गया। बाढ़, अतिवृष्टि व अन्य आपदा से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे जिला के प्रभारी मंत्री सह उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा की गया में भले हीं इस बार पितृपक्ष मेला का आयोजन नहीं हो रहा है लेकिन पिंडदान करने के लिए गयाजी पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का अतिथि देवो भवः के भाव के साथ स्वागत किया जाएगा। उनके यहां ठहरने की समुचित व्यवस्था होगी। गया शहर समेत फल्गु नदी घाटों, मंदिर परिसर में समुचित साफ-सफाई रहेगी। पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था रहेगी। पितृपक्ष में बिहार, यूपी, बंगाल समेत देश-विदेश के कोने-कोने से आने वाले पिंडदानियों के लिए हर व्यवस्था की जाएगी। ताकि गयाजी आने पर उन्हें गया और बिहार का एक अच्छा महौल महसूस हो। गयाजी से एक अच्छा संदेश लेकर वे लोग लौटें।

नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला- पिंडदानियों की समस्या को सनने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चौबीस घंटे का नियंत्रण कक्ष काम करेगा। इस बारे में जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। मेला की सभी व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन को सभी तरह का इंतेजाम करने का निदेश दिया गया है। विधि व्यवस्था दुरूस्त रखी जाएगी। पितृपक्ष मेला को लेकर बनी संशय के बीच मंत्री शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट कहा की राज्य सरकार के स्तर से मेला का आयोजन नहीं हो रहा है।

बावजूद पिंडदानियों की सेवा और सुविधा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पितृपक्ष के दौरान सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लेने को कहा गया है। कई बड़े लोग भी इस बार पितृपक्ष में गयाजी पहुंचेंगे। वह खुद भी यहां आएंगे। कोरोना के नियमों को लेकर प्रभारी मंत्री ने सभी पिंडदानियों से अनुरोध किया की शारीरिक दूरी का पालन करें। कर्मकाण्ड के दौरान मास्क

पहनकर रखें। साथ ही उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण भी करवाने को कहा।

बिहार में सुशासन की सरकार, उद्योग-रोजगार का बनने लगा माहौल- उद्योग मंत्री ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में समूचा एनडीए एकजुट होकर बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहा है। उद्योग-रोजगार का माहौल बन रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग मंत्री बनने के बाद उद्योग के लिए जो पहला प्रस्ताव लिया वह गया जिले के डोभी की कोरिडोर योजना थी। इस योजना पर काम लगातार जारी है। उस पूरे इलाके को सड़क-रेल मार्ग से जोडा जाएगा। बुनकरों को लेकर भी वह चिंतित हैं। उनसभी के विकास के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है।

बिहार की तरक्की का रास्ता गया से होकर गुजरेगा- मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार की तरक्की के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। उद्योग-पर्यटन हरेक क्षेत्र में समान गति से काम हो रहे हैं। उद्योग मंत्री और गया जिला के प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका गया पर विशेष ध्यान रहेगा। मंत्री ने कहा की गया वैसे भी धार्मिक राजधानी है। विष्णुपद, बोधगया के अलावा हजारों हज यात्री यहीं से जहाज पकड़ पर मक्का मदीना जाते हैं। गया में रोजगार सजन के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वजीरगंज व मानपुर को लेकर भी योजनाएं बनेंगी। मंत्री ने जानकारी दी कि वजीरगंज में सीमेंट उद्योग के लिए 750 करोड़ और सोलर के लिए 250 करोड़ की योजना पर काम करने का प्रस्ताव है।

वायरल बुखार को लेकर मेडिकल अफसरों को दिए निर्देश- बीते एक पखवाड़ा से जिले में वायरल बुखार के प्रभाव को लेकर मंत्री ने कहा कि मेडिकल कालेज के अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

इलाज व दवा की समुचित व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर घर पर भी बीमार लोगों की सेवा के लिए मेडिकल टीम इलाके में जाएगी। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, सहायक समाहर्ता अनुपमा सिंह, डीडीसी सुमन कुमार, एएसपी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी शंभूनाथ झा उपस्थित थे।

मप्र में अब हिन्दी में भी होगी चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई

मॉड्यूल तैयार करने बनेगी कमेटी : सारंग

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में अब मेडिकल छात्रों को हिन्दी में पढ़ाया जाएगा। पूरा कोर्स हिन्दी में ही होगा। यह घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। उन्होंने कहा कि आज हिन्दी दिवस है। सभी को इसकी शुभकामनाएं। हमने हिन्दी दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने हिन्दी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ अब हिन्दी में भी होगी। जल्दी ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक मॉड्यूल को तैयार करेगी। कमेटी के सुझाव के आधार पर ही पूरा पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाषा चयन का विकल्प छात्र के पास रहेगा कि वह किस भाषा में अपनी पढ़ाई करना चाहता है। श्री सारंग ने कहा कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा से गरीब, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करने के प्रावधान किए हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई राष्ट्र भाषा और हम सबकी मातृभाषा हिन्दी में भी हो इसके लिए जल्दी ही एक कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी एक मॉड्यूल को तैयार करेगी। इस मॉड्यूल में चिकित्सा शिक्षा का हिन्दी में पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ पाठ्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार होगा और कमेटी यह भी देखेगी की इससे कोई दूसरी व्यवहारिक परेशानी तो खड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई पहले जैसी चलती रहेगी। श्री सारंग ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी ।

शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए चलेगा महाअभियान 3.0

26 तक सभी पात्र को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने और वैक्सीन की प्रथम डोज से वंचित पात्र लोगों का शत-प्रतिशत टीकाकरण करनने टीकाकरण महाअभियान 3.0 चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर को तीसरा टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में 26 सितंबर तक वैक्सीन के प्रथम डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं।

संचालक एनएचएम टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला ने कोविड टीकाकरण महाअभियान 3.0 में पहले दिन 32 लाख 90 हजार टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शुक्ला के मुताबिक कोविड टीकाकरण महाअभियान 3.0 में धार जिले को 2 लाख, इंदौर को एक लाख 65 हजार, सतना को एक लाख 45 हजार, उज्जैन एक लाख 43 हजार, भोपाल एक लाख 21 हजार, सागर एक लाख 19 हजार 700, छिंदवाड़ा एक लाख 4 हजार 700, रीवा एक लाख, खरगोन 96 हजार 300, ग्वालियर 94 हजार 300, भिंड 88 हजार, शिवपुरी 84 हजार 400, मुरैना 83 हजार 100, विदिशा 77 हजार, देवास 75 हजार, मंदसौर 69 हजार 900, बालाघाट 66 हजार, बैतूल 66 हजार, छतरपुर 65 हजार 900, रायसेन 65 हजार 300, राजगढ़ 64 हजार 300, बड़वानी 62 हजार 100, सिवनी 61 हजार 900, जबलपुर 60 हजार, सिंगरौली 56 हजार 100, सीधी 55 हजार 700, टीकमगढ़ 55 हजार 600, कटनी 55 हजार, रतलाम 55 हजार, खंडवा 52 हजार 700, शहडोल 49 हजार 600, होशंगाबाद 48 हजार 100, सीहोर 47 हजार 500, दमोह 44 हजार, नरसिंहपुर 42 हजार, पन्ना 41 हजार 600, मंडला 38 हजार 500, गुना 36 हजार 700, बुरहानपुर 34 हजार 100, झाबुआ 32 हजार 300, अशोकनगर 31 हजार 600, अलीराजपुर 29 हजार, दतिया 28 हजार 100, शाजापुर 27 हजार 600, डिंडौरी 25 हजार 700, उमरिया 24 हजार 700, हरदा 22 हजार, श्योपुर 22 हजार, नीमच 22 हजार, अनूपपुर 20 हजार और आगर जिले के लिए लगभग 15 हजार का लक्ष्य दिया गया है। एनएचएम संचालक टीकाकरण ने बताया कि अब तक एक दिन में सवार्धिक 28 लाख 50 हजार कोविड-19 टीके लगाने का रिकॉर्ड है। टीकाकरण महाअभियान 3.0 में 32 लाख 90 हजार टीके लगाने का नया रिकॉर्ड होगा।

सीएम आज करेंगे डेंगू प्रहार महाअभियान का शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेशवासियों से की सहयोग की अपील

भोपाल (एजेंसी)। डेंगू, चिकुनगुनिया पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार, 15 सितंबर को प्रांतव्यापी डेंगू प्रहार महाअभियान का शुभारंभ भोपाल से कर रहे हैं। डेंगू प्रहार महाअभियान में लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

डॉ. चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित नागरिकों और आम नागरिकों से अभियान में सहयोग की अपील की है । उन्होंने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के समन्वय से महाअभियान संचालित कर रहा। उन्होंने कहा कि महाअभियान आप सबकी सहभागिता से सफल होगा। हम डेंगू पर नियंत्रण करने में सफल होंगे । मंत्री डॉ. चौधरी ने नागरिकों से आग्रह है कि डेंगू की रेपिड रिस्पांस टीम आपके क्षेत्र में आए तो उसका सहयोग करें। अपने घरों के आसपास के डेंगू मच्छरों के लार्वा को पैदा करने वाले साफ जमा पानी के पात्रों से पानी हटा दें। एक सप्ताह तक साफ पानी जमा नहीं रहने दें। डेंगू प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम से कीटनाशक का छिड़काव करवाना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि सितंबर माह में रूक-रूक के वर्षा होने से पानी घर के आस-पास गमले, टायर, कूलर और अन्य पात्रों में साफ पानी जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मच्छरों को पैदा करने वाले लार्वा जमा साफ पानी में पनपते हैं। हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारी छोटी सी गलती के चलते डेंगू के मच्छर पनपते हैं। उन्होंने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वह अपने घर के आस-पास स्वच्छ पानी को जमा नहीं होने दें।

डेंगू का उपचार है, डरने की जरूरत नहीं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि डेंगू और चिकुनगुनिया के उपचार को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के योजना में इनपैनल्ड 867 शासकीय और निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। आम नागरिक भारत निरामयम योजना में उपचार की जानकारी टोल फ्री नंबर 14555 और 18002332085 पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डेंगू की जांच की व्यवस्था है। डॉ. चौधरी ने नागरिकों से कहा है कि डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है। डेंगू का उपचार है।

जनदर्शन वाले क्षेत्र में अफसरों को भारी पड़ी लापरवाही

सीएम ने सीएमओ, उपयंत्री को किया तत्काल सस्पेंड, तहसीलदार भी नपे

पृथ्वीपुर विधानसभा के जैरोन में जनसभा के दौरान किया सस्पेंड कहा, जेल भी भिजवाऊंगा

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन कार्यक्रम के सिलसिले में मंगलवार को टीकमगढ़ जिले में पहुंचे। यहां पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांवों में जनदर्शन कर लोगों से संवाद किया और जनसभा को संबोधित भी किया। यह जनदर्शन अब लापरवाह अफसरों को भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री मौके पर ही अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। कुछ इस तरह के घटनाक्रम में जैरोन की जनसभा में प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी पर उन्होंने सीएमओ और उपयंत्री को सस्पेंड करने की घोषणा की। इधर पृथ्वीपुर में भी लापरवाही पर तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सागर संभागायुक्त ने सीएमओ निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए।

जैरोन में जनसभा के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली। उन्होंने तत्काल ही अफसरों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि कौन है सीएमओ अभी, इधर आओ। ये मकान कब स्वीकृत हुए थे? 2017-18 में सीएमओ कौन था? मैं पूछ रहा हूं कि मकान बनें या नहीं बने, बताइए क्यों नहीं बने? आप इधर आओ, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार किसने किया। अभी नाम बताओ, मैं अभी उसे सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा। छोडूंगा किसी को नहीं।

सीएम ने फिर चैताया भैया सुन लो, अभी जो मैं बता रहा हूं नोट कर लेना। कोई उमाशंकर उपयंत्री था, कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था। ये बता रहे हैं ये लोग मुझे- सही है क्या? उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है, जहां भी हों। अब इसकी जांच होगी, केवल सस्पेंड नहीं, ईओडब्ल्यू से जांच कराके जिसने पैसा खाया है, उसे जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए हम पैसा भिजवाते हैं और ये हड़प जाते हैं, कमिश्नर कब आएंगे, इसकी जांच पूरी करने। उन्होंने कहा कि दो दिन बाद आईये, जांच कीजिए पूरी, यहीं चौपाल पर जांच होगी। इधर पृथ्वीपुर में भी लापरवाही पर उन्होंने तहसीलदार अनिल तालिया को भी निलंबित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लगभग सात घंटे तक जनदर्शन किया।

ओरछा में खुलेगा महाविद्यालय

सीएम ने श्री राम राजा सरकार के दर्शन के बाद की घोषणा

भोपाल, (प्रसं)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री राम राजा की नगरी ओरछा में आगामी शिक्षण-सत्र से महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में जनदर्शन कार्यक्रम के लिएओरछा पहुंचे। उन्होंने यहां श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राम राजा सरकार के दर्शन करके राधाष्टमी के दिन हम जनदर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी राम राजा के दर्शन कर उनसे यही प्रार्थना की है कि मप्र की जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हों। उन्होंने कहा कि मैंने यह भी कामना की है कि कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और फिर हम विकास के पथ पर प्रदेश को तेजी से आगे ले जाकर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बना पाएं।

मांग कर खाने वाले और कचरा बीनने वालों को भी मिलेगा नि:शुल्क राशन

मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने दी जानकारी

भोपाल (एजेंसी)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता श्रेणी मांग कर खाने वाले एवं कचरा बीनकर जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति एवं उसके परिजन को निःशुल्क राशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे गरीब हितग्राहियों को अन्य वंचित वर्ग के परिवारों के सत्यापन के लिए राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार अन्य वंचित वर्ग को नवीन प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राहियों का सत्यापन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मांग कर भरण-पोषण करने वाले तथा कचरा उठाने वाले गरीब व्यक्ति एवं उनके ऐसे परिवार, जो किसी भी अन्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, को शामिल किया जा सकेगा।

कांग्रेस के सचिव सुधांशु त्रिपाठी कल गुना दौरे पर

भोपाल, (रासं)। अभा कांग्रेस के सचिव सहप्रभारी सुधांशु त्रिपाठी 16 सितंबर को गुना जिले के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। श्री त्रिपाठी 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे गुना पहुंचेंगे और वहां पर जिला, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों, स्थानीय विधायक, विधानसभा प्रत्याशियों 2018, जिला प्रभारी के साथ मंडलम सेक्टर गठन एवं संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे।

कमलनाथ ने की सरकार से फैसला वापस लेने की मांग

भोपाल । प्रदेश के छतरपुर के 130 वर्ष पुराने महाराजा महाविद्यालय के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि में संविलियन के निर्णय को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरी तरह से गलत व क्षेत्र की जनता की भावनाओं के विपरीत बताया है। नाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शिवराज सरकार ने नौ वर्ष पूर्व छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया था, सरकार अपने वादे को आज तक पूरा नहीं कर सकी है, इसके लिए सरकार ने आज तक कोई बजट जारी नहीं किया, जिससे विश्वविद्यालय का आज तक निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका और सरकार ने अब अपनी इस वादाखिलाफी पर पर्दा डालने के लिए यह जनविरोधी निर्णय लिया है। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने इस जनविरोधी फैसले को तत्काल वापस ले और महाराजा महाविद्यालय को यथावत रखते हुए, अपनी पूर्व की घोषणा अनुसार छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि के निर्माण के लिए बजट जारी कर इसका निर्माण प्रारंभ करवाए।

सहायता राशि की घोषणा कर कोरोना मृतकों के परिजनों को भूली सरकार

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक लाख की सहायता राशि दिए जाने के सरकार की घोषणा के बाद भी आज तक किसी को यह राशि न मिलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूव मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर घोषणा कर मृतकों के परिजनों को भूलने का आरोप लगाया है।

कमलनाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के कारण असमय कालकवलित हुए नागरिकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि की घोषणा सरकार द्वारा मई 2021 में की गई थी, परंतु आज तक एक भी परिवार को सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। परिजनों की मृत्यु के बाद अब परिवार के लोग अनुग्रह सहायता राशि की आस लगाए बैठे हैं और सरकार की योजना और सहायता राशि के कोई अते-पते नहीं हैं।

नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार घोषणाएं करके भूल जाती है, इस घोषणा को किए चार माह का समय हो गया है और अब तक न तो सरकार ने कोई योजना जारी की है और न ही किसी पीड़ित परिजन को सहायता राशि देकर संबल प्रदान किया है, कोरोना पीड़ित परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण मात्र कोरी घोषणा बनकर रह गया है। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि कोरोना मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति दिखाए और मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि का वितरण कराए। सरकार मृतकों के परिजनों के शपथ-पत्र के आधार पर ही सहायता राशि वितरित करे ताकि सभी पीड़ितों के परिवारों को तत्काल मदद मिल सके।

इस साल खुलेंगे तीन लाख स्कूल और बनेंगे आठ लाख आवास

मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में जनदर्शन कार्यक्रम को किया संबोधित

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब का अपना पक्का आवास होगा। वर्ष 2011 की सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 8 लाख आवास फिर अगले साल 8 लाख आवास बनाए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कोई गरीब बिना मकान के न रहे।

मुख्यमंत्री टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ में मंगलवार को जनदर्शन कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहित सभी सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 300 स्कूल खोले जाएंगे। अगले सत्र में पुनः 300 स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों की सरकार है। हम सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अजा - जजा में भेद भाव किए बिना समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब को रोटी मिल जाए इसलिए सरकार ने तय किया है कि एक रुपऐ किलो गेहूं, चावल, नमक उन्हें दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है, जो जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को अन्न देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि पात्रता पर्ची से वंचित रहे परिवारों का सर्वे कराकर नाम जोड़े जाएं। गरीबों के लिए सरकार के खजाने खुले हैं। चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत हो गई है। शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसमें टीकमगढ़ जिले की लाखों हेक्टयेर कृषि भूमि में सिंचाई होगी।

टीकमगढ़ जिले का मेहनती किसान अधिक फसल पैदा कर सकें, इसका इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा मोहनगढ़ के हथेरी, पंचमपुरा, कुंजपुरा आदि गांवों में पीने के पानी की दिक्कत होती थी। अब हमने तय किया है सभी गांवों को हेंडपंप से मुक्ति दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनता के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के करीब दो हजार किसान प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री सम्मान निधि से छूटे हुए हैं, एक सप्ताह के भीतर उनके नाम जोड़कर उनके खातों में राशि डाली जाएगी।

सीएम ने वितरित किए 32 करोड़ के हितलाभ

चौहान ने कहा कि मोहनगढ़ में निषादराज भवन का निर्माण कराया जाएगा। मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन कराया जाएगा, जिससे मोहनगढ़ और आस-पास की जनता का यहां इलाज संभव हो सके। उन्होंने कहा कि हरपुरा सिंचाई परियोजना नहर के पुनर्निर्माण का फैसला किया है,जो चंदेली तालाबों को भी भरेगा। इन तालाबों को भरने का अभियान फिर से चलाया जायेगा। हरपुरा नहर का 11 करोड़ 41 लाख रुपए से पुनर्निर्माण किया जाएगा, इससे क्षेत्र के गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किए।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वीसी के जरिए सभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से किया संवाद

होमगार्ड के डाइंग कॉडर रिव्यू के लिए कमेटी होगी गठित

डीजी होमगार्ड जैन ने कहा, एसडीईआरएफ के जवानों के जबलपुर में बनाया जा सकता है प्रशिक्षण संस्थान

भोपाल (एजेंसी)। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय के राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के जिला सेनानी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से संवाद किया। उन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए श्योपुर, ग्वालियर, रायसेन, अशोकनगर, इंदौर और उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट से सुझाव प्राप्त किए। डॉ. मिश्रा ने होमगार्ड और स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीईआरएफ) की बेहतरी के लिए रिव्यू कमेटी के गठन के निर्देश दिए। कमेटी में गृह मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव गृह, महानिदेशक होमगार्ड और प्रमुख सचिव वित्त शामिल रहेंगे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में होमगार्ड के जवानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इस स्थिति में होमगार्ड के कॉडर को डाइंग घोषित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन के लिये जरूरी अन्य विषयों पर भी निर्णय लिया जाएगा। निर्णयों से शासन को अवगत कराया जाकर उन्हें अमलीजामा पहनाया जाएगा। बैठक के पूर्व होमगार्ड के नव-नियुक्त महानिदेशक पवन कुमार जैन ने आपदा प्रबंधन के लिए एसडीईआरएफ के जवानों के बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि जबलपुर के मुंगेली में विभाग के पास मौजूद 206 हेक्टेयर भूमि में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सकता है। श्री जैन ने कहा कि गृह मंत्री डॉ. मिश्रा के कार्यकाल में विभागीय संस्थानों के उन्नयन के लिये कई महती कार्य किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। जबलपुर में प्रशिक्षण संस्थान के लिए पूर्व में 176 करोड़ रुपए का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। डॉ. मिश्रा ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में वे स्वयं मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से चर्चा करेंगे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा का स्वागत करते हुए महानिदेशक श्री जैन ने उन्हें भारत-माता का सच्चा हिन्दी पुत्र बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय वीसी में डॉ. मिश्रा की मौजूदगी सभी के लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी है। श्री जैन ने कहा कि दतिया के कोटरा में बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू करते हुए डॉ. मिश्रा ने जो किया, वह हमारे जवानों के लिए प्रेरणादायी होकर हौसला बढ़ाने वाला है। एडीजी होमगार्ड डीपी गुप्ता, एडीजी अशोक अवस्थी, सचिव गृह रवींद्र सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

किसान कांग्रेस का चंबल में चरणबद्ध आंदोलन आज से

प्रदेश सरकार से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की करेंगे मांग

भोपाल (एजेंसी)। मप्र किसान कांग्रेस चंबल संभाग में चरणबद्ध आंदोलन का 15 सितंबर को श्योपुर से शंखनाद करेगी। आंदोलन की अगुवाई किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर करेंगे। आंदोलन में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा, किसानों की बाढ़ में नष्ट हुई फसलों का तुरंत मुआवजा की मांग तथा महंगाई के विरोध में आंदोलन है। उक्त आशय की जानकारी मप्र किसान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी फिरोज सिद्दीकी ने दी है।

श्योपुर में आंदोलन के आयोजक कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल करेंगे। उसके उपरांत 16 सितंबर को गोहद जिला भिंड में कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव द्वारा आयोजित आंदोलन में दिनेश गुर्जर व किसान कांग्रेस के पदाधिकारी, हजारों किसान भाग लेंगे, 21 सितंबर को मुरैना के आंदोलन में पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा किसानों व किसान कांग्रेस के साथ आंदोलन में भाग लेंगे तथा श्री वर्मा के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्टर को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे।

सिद्दीकी ने बताया कि इसी दिन 21 सितंबर दोपहर एक बजे सज्जन सिंह वर्मा व दिनेश गुर्जर भिंड में आंदोलन का समापन करेंगे। आंदोलन को चरणबद्ध चलाकर भाजपा सरकार को किसान कांग्रेस जगाएगी। यदि सरकार इस आंदोलन के बाद भी नहीं जागती है तो इस आंदोलन को जन-जन तक किसान कांग्रेस लेकर जाएगी।

लाल साड़ी में

जैकलीन फर्नांडिस

ने ढाया कहर, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) इन दिनों फिल्म भूत पुलिस (Bhoot Police) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में जैकलीन, भूत पुलिस को प्रमोट करन डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) के सेट पर पहुंची। लाल साड़ी में जैकलीन ने अपनी अदाओं से सभी का दिल जीत लिया, इस बीच उनकी साड़ी की कीमत सामने आई है।

54 हजार से अधिक है साड़ी की कीमत

दरअसल हाल ही में जैकलीन की डिजाइनर चांदनी व्हाबी ने अपने सोशल मीडिया पर जैकलीन की लाल रूबी शीर साड़ी पहने हुए तस्वीर शेयर की। साड़ी में जैकलीन काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। ऐसे में अब इस साड़ी की कीमत सामने आ गई है। बता दें कि Surkh Farrin साड़ी की कीमत 54 हजार 500 रुपये है।

ईडी ने दर्ज किया था स्टेटमेंट

याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर चर्चा में थीं और ईडी ने उनका स्टेटमेंट भी दर्ज किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में जैकलीन से गवाह के तौर पर बयान लिया गया और उनसे एक पीड़ित के तौर पर पूछताछ की गई थी। इस केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है। सुकेश पर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज की थी। उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप है। ईडी सोर्सेज के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को तिहाड़ जेल से कॉलर आईडी स्पूफिंग के जरिए झांसा दिया।

जैकलीन की फिल्में

बता दें कि जैकलीन की फिल्म भूत पुलिस हाल ही में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकलीन के साथ अर्जुन कपूर, सैफ अली खान और यामी गौतम अहम किरदारों में हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिलाजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं जैकलीन जल्दी ही सर्कस, राम सेतू और बच्चन पांडे में नजर आएंगी। सर्कस में जैकलीन के साथ रणवीर सिंह प्रमुख भूमिका में दिखेंगे जबकि बच्चन पांडे में अक्षय कुमार। वहीं राम सेतू में जैकलीन के साथ अक्षय और नुसरत भरूचा नजर आएंगी।

सारा अली खान ने बोल्ड अंदाज से ढाया कहर, कैप्शन से दी जिंदगी के लिए बड़ी सीख

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान (Sara Ali Khan) इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैन्स काफी पसंद करते हैं। ऐसे में एक बार सारा ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं।

सारा की मालदीव फोटो

सारा ने इंस्टा पर अपनी मालदीव की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक ओर जहां सारा काफी क्यूट दिख रही हैं तो वहीं हॉटनेस का भी पारा वो बढ़ाती दिख रही हैं। तस्वीरों के साथ सारा ने कैप्शन में लिखा, हर दिन आप जो फसल काटते हैं, उसके मुताबिक नहीं बल्कि जो बीज आप लगाते हैं, उसके मुताबिक देखें। बता दें कि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की कही हुई ये बात जिंदगी के लिए बड़ा सबक है।

अक्सर वायरल होते हैं सारा के फोटोज- वीडियोज

बता दें कि सारा अली खान अक्सर अलग- अलग अंदाज और मौको पर अपने फोटोज-वीडियोज शेयर करती हैं। सारा के फोटोज भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं। चाहें देसी अवतार की बात हो या फिर बोल्ड अंदाज की, सारा का हर स्टाइल फैन्स को पसंद आता है।

https://www.instagram.com/p/CSMXDBJjtYt/

सारा का फिल्मी करियर

याद दिला दें कि सारा अली खान ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद सारा फिल्म सिंबा में रणवीर सिंह के साथ नजर आईं। वहीं सारा की तीसरी फिल्म कार्तिक आर्यन के साथ लव आज कल थी। इसके साथ ही सारा आखिरी बार वरुण धवन के साथ फिल्म कुली नंबर वन में दिखी थीं। सारा अली खान जल्दी ही फिल्म अतरंगी रे में नजर आएंगी। इस फिल्म में सारा के साथ अक्षय कुमार और धनुष मुख्य किरदारों में दिखेंगे।

हाथ में असली गन लेकर डांस करती दिखीं उर्वशी रौतेला, वायरल वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

उर्वशी रौतेला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उर्वशी रौतेला असली वाला बंदूक लिए डांस करती दिख रही हैं। इंटरनेट की सेंसेशन गर्ल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है।

उर्वशी रौतेला इस वीडियो को कई सारी लॉफिंग इमोजी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखती हैं- बॉयज पूरी मस्ती करनी चाहिए इम्प्रॉम्प्टू टच असली गन के साथ। वीडियो में उर्वशी 'Shut Up and Bend Over' सॉन्ग पर गजब का डांस करती दिख रही हैं। वीडियो में उर्वशी का डांस मूव्स को देखकर उनके चाहने वाले फिदा हो गये हैं। एक घंटे पहले शेयर किये गये इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

उर्वशी रौतेला बॉलीवुड में अपने स्टाइल और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। परफेक्ट बॉडी के लिए उर्वशी रौतेला को कई एक्ट्रेसेस फॉलो करती हैं। इंस्टाग्राम पर भी उर्वशी रौतेला की एक तस्वीर पर लाखों लाइक मिलते हैं। इससे पहले उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट करते हुए अपने अपने चाहने वालों को थैंक्यू नोट लिखी थीं। अदाकारा के इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जिसका जश्न मनाते हुए उन्होंने केक काटकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया और लोगों को धन्यवाद कहा था । आने वाले दिनों में उर्वशी रौतेला के पास बैक टू बैक कई फिल्में हैं। जल्द ही वह वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में नजर आयेंगी। उर्वशी रौतेला और रणदीप हुड्डा की जोड़ी इसमें दिखाई देगी। बाकी साउथ में ब्लैक राजा रिलीज होगी। अभी हाल ही में उर्वशी रौतेला म्यूजिक वीडियो वर्साच बेबी और एक लड़की भीगी भागी सी में नजर आयी थीं।

नरगिस फाखरी

ने उदय चोपड़ा से डेटिंग पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, रिश्ता छुपाने की बताई वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने रिलेशनशिप को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. कई बार लव लाइफ को लेकर तो कई बार ब्रेकअप की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) जिन्होंने बरसों बाद अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया है. नरगिस ने पहली बार माना कि एक्टर प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा (Uday Chopra) को लंबे समय तक डेट किया था. नरगिस से इस रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में या फैंस से कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था.

टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नरगिस फाखरी ने उदय चोपड़ा के संग रिलेशनशिप के दिनों को याद करते हुए कहा 'वह एक शानदार शख्सियत हैं और मुझे अफसोस है कि मैंने उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बोला. उदय और मैंने करीब 5 साल एक दूसरे को डेट किया.

इंडिया में अब तक मैं जितने लोगों से मिली हूं, उसमें वह सबसे अच्छे इंसान हैं. मैंने इसके बारे में कभी मीडिया से बात नहीं की, क्योंकि लोगों ने मुझे इस पर चुप रहने की सलाह दी थी, लेकिन अब मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि मैं पहाड़ की ऊंचाई से चिल्ला कर कहना चाहती थी कि मैं एक इतने अच्छे इंसान के साथ हूं'. इतना ही नहीं, नरगिस ने सोशल मीडिया को फेक बताया है.

हालांकि मीडिया में सन 2014 में नरगिस फाखरी और उदय चोपड़ा के अफेयर की खबरें सामने आई थी, लेकिन दोनों ने हमेशा इससे इनकार किया. यह पहला मौका है जब नरगिस ने उदय के संग अपने रिलेशनशिप को माना है. 'मिड डे' को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि 'मैं एक बार फिर कहती हूं कि मैं और उदय एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, लेकिन वह हमेशा मेरी लाइफ का हिस्सा रहेंगे. इंडिया में मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि उनमें से वह भी एक हैं'.

उदय चोपड़ा से ब्रेकअप के बाद नरगिस फाखरी न्यूयॉर्क चली गईं थीं. ऐसे में लोगों को लगा था कि एक्ट्रेस ने दिल टूटने के बाद देश छोड़ दिया, लेकिन उनके प्रवक्ता ने इस फैसले के पीछे उनकी सेहत बताई थी.

मिताली राज की बादशाहत कायम

नई दिल्ली। आईसीसी ने महिलाओं की वन-डे रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय वन-डे टीम की कप्तान मिताली राज की बादशाहत कायम है। वह 762 रेटिंग के साथ नंबर पर बरकरार हैं। मिताली के साथ-साथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लिजेल ली (762 रेटिंग) को एक स्थान का फायदा हुआ है। इसके साथ वह शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली और ली दोनों संयुक्त रूप में पहले स्थान पर काबिज हैं। हाल ही में ली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 91 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिग में हुआ है। बता दें कि साल 2018 जून के बाद ली ने पहली बार शीर्ष स्थान हासिल की हैं। रैंकिग में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली (756 रेटिंग) हैं। मिताली के अलावा टॉप 10 में केवल एक भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं। मंधाना को रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है। वह 701 रेटिंग के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में दो भारतीय शामिल हैं। झूलन गोस्वामी 694 रेटंगि के साथ पांचवें स्थान पर जबकि पूनम यादव (617 रेटिंग) नौवें स्थान पर बरकरार हैं। उधर, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वह 418 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, भारत की दीप्ति शर्मा 331 रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर बनी हुई हैं।

वोक्स ने टी-20 लीग में शामिल नहीं होने पर तोड़ी चुप्पी, इन दो टूर्नामेंट को बताया महत्वपूर्ण

कोलंबो। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के बाद अधिकतर भारतीय खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड के तीन बड़े खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा करने वालों में दिल्ली कैपिटल्स के क्रिस वोक्स भी शामिल हैं। वह भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे लेकिन उन्होंने यूएई में वाली टी-20 लीग में शामिल होने से मना कर दिया। वोक्स ने हालांकि अपने इस फैसले पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। वोक्स ने कहा, 'लगातार तीन टूर्नामेंट खेलना बेहद कठिन है, इसलिए उन्होंने आईपीएल की बजाय टी-20 वर्ल्ड कप और एशेज में हिस्सा लेने का फैसला किया।'

इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने दी गार्जियन से बातचीत में कहा, 'मुझे नहीं लगा था कि वर्ल्ड कप स्क्वॉड में मेरा नाम शामिल किया जाएगा, खासकर दो महीने पहले। आईपीएल को रिशेड्यूल किया गया और हमारे समर सीजन के अंत में रख दिया गया। वर्ल्ड कप और एशेज, यह कम समय में बहुत है। मैं आईपीएल में शामिल होकर खुश होता लेकिन किसी एक छोड़ना था।' गौरतलब है कि वोक्स ने एशेज में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की इच्छा जताई थी, वो भी तब जब कई ब्रिटिश खिलाड़ियों कोविड-19 पाबंदियों को लेकर चिंतित थे। बात करें आईपीएल की तो 14वें सीजन के दूसरे चरण का आयोजन 19 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। यही नहीं इसके बाद अगले महीने से टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी यहीं होना है।

आईपीएल से पहले गंभीर ने विराट को लेकर दिया बयान, कहा- कोहली के लिए अलग चुनौती

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे सत्र की शुरुआत होने में पांच दिन बाकी हैं। आईपीएल के दूसरे सत्र का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है जो 19 सितंबर से शुरू होगा। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट गौतम गंभीर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली सहित एबी डिवीलियर्स को लेकर बयान दिया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज का मानना है कि आईपीएल के दौरान विराट और डिवीलियर्स दबाव में होंगे क्योंकि उनके लिए यह अलग चुनौती होगी।

ये दोनों क्रिकेटर न सिर्फ आरसीबी के सबसे अनुभवी क्रिकेटर हैं बल्कि अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं। स्टार स्पोर्ट से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली को अपने खेल के जल्दी से समायोजित करना होगा और उन्हें टी-20 के मोड में आना होगा। कोहली इंग्लैंड के खिलाफ लंबी टेस्ट सीरीज खेलकर वापस आए हैं उनका ध्यान लाल गेंद की स्विंग पर होगा, लेकिन आईपीएल में उन्हें जल्द से जल्द रन बनाना होगा। गंभीर ने आगे कहा, विराट कोहली के लिए एक चुनौती होने वाली है और इस चुनौती की सामना एबी डिविलियर्स को करना होगा क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज बिना कोई टूर्नामेंट खेलेल आईपीएल में आएंगे।

टोक्यो ओलंपिक:खराब प्रदर्शन के बाद एएफआई ने श्रीशंकर के कोच को किया बर्खास्त

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में लंबी कूद के खिलाड़ी एम श्रीशंकर के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने उनके कोच एस मुरली को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि मुरली कोच के साथ-साथ शंकर के पिता भी हैं।

इस मामले में एएफआई अध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने कहा, 'हम उसके कोचिंग कार्यक्रम से खुश नहीं हैं, पहली कार्रवाई हो चुकी है और हमने उसका कोच बदल दिया है।' गौरतलब है कि मार्च में फेडरेशन कप में 8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ क्वालीफिकेशन स्तर हासिल करने वाले 22 साल के श्रीशंकर टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले फिटनेस ट्रायल में बुरी तरह नाकाम रहे, जिसके बाद एएफआई को उन्हें खेलों से हटाने के बारे में विचार करना पड़ा। यहां कार्यकारी परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद एएफआई ने साथ ही कहा कि ओलंपिक और

विश्व चैंपियनशिप से पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तरह का टूर्नामेंट या फाइनल ट्रायल का आयोजन करके इन टूर्नामेंटों के लिए टीम का चयन किया जाएगा।

दुखदः भारत के पूर्व फुटबॉलर भबानी रॉय का निधन, 1969 में मर्डेका कप में किया था देश का प्रतिनिधित्व

सिडनी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर भबानी रॉय का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रॉय पिछले कुछ दिनों से शहर के अस्पताल में भर्ती थे। रॉय ने 1969 में मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

रॉय घरेलू स्तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा रहे। वह 1968 से मोहन बागान की तरफ से क्लब फुटबॉल खेले। उन्होंने 1972 में टीम की कप्तानी की जो टीम के साथ उनका अंतिम साल था। रॉय ने अपने करियर की शुरुआत बागान के चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल के साथ 1964 में की थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने रॉय के निधन पर शोक जताया है। एआईएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'भबानी रॉय के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। भारत में खेल में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं काफी दुखी हूं।'

बैनः जर्मनी के इस फुटबॉलर पर लगा प्रतिबंध, मैच के दौरान की थी नस्लीय टिप्पणी

नई दिल्ली। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी डेनिस एर्डमैन को मैच के दौरान विपक्षी खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने का दोषी पाया गया है। जिसके चलते उन पर आठ सप्ताह का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने तीसरे डिवीजन खेल के दौरान यह विपक्षी खिलाड़ियों के विरुद्ध नस्लीय टिप्पणी की। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद उन पर यह बैन लगाने का फैसला लिया गया।

मैगडेबर्ग के खिलाड़ियों ने डेनिस एर्डमैन पर नस्लवादी अपमान करने का आरोप लगाया जब वह पिछले महीने सारब्रुकन के लिए उनके खिलाफ खेले थे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जर्मन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से स्टीफन ओबरहोल्ज ने कहा, संघ अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नस्लवाद और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है और यहां भी एक कड़ी कार्रवाई करने के बाद स्पष्ट

संदेश भेज रहा है।

एर्डमैन सुनवाई से पहले अस्थाई रूप से निलंबित होने पर पहले ही दो मैच खेलने से चूक गए थे। वहीं, 30 वर्षीय डिफेंडर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। जबकि, सारब्रुकन का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

यूएस ओपन चैंपियन रूसी मेदवेदेव और ग्रीक खिलाड़ी सितसिपास ने पक्की की जगह

नई दिल्ली। यूएस टेनिस ओपन की समाप्ति के साथ ही साल का आखिरी मेजर टूर्नामेंट भी खत्म हो गया है। इस बार के अमेरिकी ओपन में रूस के स्टार खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव विजेता बने जबकि सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही मेदवेदेव और एटीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज स्टेफनोस सितसिपास ने एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

तुरीन में 14-21 नवंबर तक होने वाले एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में जगह बनाने वाले मेदवेदेव और सितसिपास क्रमशः दूसरे और तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले जोकोविच ही एकमात्र खिलाड़ी थे जिसने अपनी जगह पक्की की थी।

गत विजेता मेदवेदेव इस बार अपने खिताब को बचाने के लिए उतरेंगे। वह लंदन में पिछले साल खेले गए टूर्नामेंट में विजेता थे।

मेदवेदेव के इस साल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इसी साल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग हासिल की थी। इसके अलावा उनका इस बार का जीत-हार का रिकॉर्ड भी 47-10 का रहा जिसमें यूएस ओपन की खिताबी जीत भी शामिल है।

बात करें सितसिपास की तो यूएस ओपन के तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गए लेकिन इससे पहले उन्होंने मोंटे कार्लो में मास्टर्स 1000 का खिताब जीता। इसके अलावा वह फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने एटीपी 250 का खिताब अपने नाम किया।

दो टूकः कोहली की कप्तानी पर बोले राजीव शुक्ला, कहा- लोग कप्तान की भविष्यवाणी करने के बजाय विश्व कप पर ध्यान दें

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने क्रिकेट के सीमित प्रारूप में विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बयान दिया है।

बीसीसीआई वाइस प्रेसीडेंट उन अफवाहों से प्रभावित नहीं हैं जिनमें कहा गया कि भारतीय टीम संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले टी-20 विश्व के बाद लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए कप्तान बदलने के बारे सोच रही है। इन अफवाहों को राजीव शुक्ला ने बकवास करार दिया और कहा हमें विश्व कप ध्यान देना चाहिए।

स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर कोई बात नहीं

कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा गया था कि टी-20 विश्व कप के बाद रोहित शर्मा सीमित प्रारूप के कप्तान बन सकते हैं जबकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी जारी रखेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि टीम का फोकस इस समय विश्व कप पर है, उन्होंने कहा, कप्तान की भविष्यवाणी करने के बजाय विश्व कप पर ध्यान देना चाहिए, स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बीते बुधवार को बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया था। सिलेक्टर द्वारा घोषित की गई विश्व कप टीम में रोहित शर्मा को उपकप्तान बनाया गया।

यूएस ओपन चैंपियन एमा ने लगाई 127 स्थान की छलांग, लेलाह को भी जबरदस्त फायदा

न्यूयार्क। यूएस ओपन में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली 18 साल की एमा रादुकानू ने एटीपी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई हैं। अमेरिकी ओपन की नई चैंपियन एमा 127 स्थान की उछाल के साथ 23वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, कनाडा की 19 साल की लेलाह फर्नांडिज रैंकिंग में 45 स्थान की उछाल के साथ 28वें पायदान पर पहुंच गई हैं। बता दें कि बीते दिनों ब्रिटेन की एमा ने यूएस ओपन चैंपियन बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। एमा टेनिस इतिहास में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बन गईं। दुनिया की 150वें नंबर की खिलाड़ी 18 वर्षीय एमा कनाडा की 19 साल

की लेलाह फर्नांडिज को एक घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से मात देकर विजेता बनीं। इसी के साथ एमा टेनिस इतिहास में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बन गईं।

शीर्ष पांच में बदलाव, ओसाका पांचवें स्थान पर पहुंचीं

वहीं, रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी 10075 अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। दूसरे नंबर पर बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका (7720 अंक) काबिज हैं। वहीं, चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा (5315 अंक) और यूक्रेन की एलीना स्वितोलिना को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। प्लिसकोवा तीसरे स्थान पर जबकि स्वितोलिना 4860 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, जापान की नाओमी ओसाका दो दो स्थान का नुकसान हुआ है। वह पांचवें स्थान (4796) पर खिसक गई हैं।

रोनाल्डो के दो गोल के दम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की शानदार जीत, न्यूकैसल को 4-1 से हराया

मैनचेस्टर। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से अपनी दूसरी पारी का शानदार आगाज किया है। रोनाल्डो के दो गोल के दम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शनिवार को न्यूकैसल को 4-1 से हराया। रोनाल्डो ने पहला गोल 45+2वें मिनट में जबकि दूसरा गोल 62वें मिनट में किया। बता दें कि मैच में रोनाल्डो ने 45+2वें मिनट में शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसी के साथ पहला हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम रहा है। वहीं, दूसरे हाफ में न्यूकैसल की तरफ से जैवियर ने 56वें मिनट में गोल किया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद रोनाल्डो 62वें मिनट में ओक और गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। वहीं, खेल के 80वें मिनट में

ब्रुनो फर्नांडिस ने मैनचेस्टर के लिए एक और गोलकर टीम को 3-1 से बढ़त दिला दी। इसके बाद 90+2वें मिनट में जेसी लिंगार्ड ने एक और गोल दागा। इसी के साथ मैनचेस्टर की टीम यह मुकाबला 4-1 से अपने नामकर ली। गौरतलब है कि रोनाल्डो की 12 साल बाद पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी हुई है। क्लब ने रोनाल्डो के साथ दो साल का करार किया है।

कार्यकालः भाला फेंक के मुख्य कोच उवे हॉन हटाए गए, एएफआई ने कहा- प्रदर्शन से खुश नहीं थे

मुंबई। टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो चुका है। भारत के लिहाज से इस बार का ओलंपिक बेहद खास रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार रिकॉर्ड सात पदक जीते जिसमें आखिरी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया।

नीरज की सफलता के पीछे उनके कोच उवे हॉन का बड़ा योगदान था। हालांकि ओलंपिक की समाप्ति के बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने नीरज के कोच उवे हॉन से नाता तोड़ दिया है।

एएफआई ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भाला फेंक के राष्ट्रीय कोच उवे हॉन से नाता तोड़ दिया है। एएफआई ने बताया

कि वह कोच के प्रदर्शन से खुश नहीं था और अब जल्द ही दो नए विदेशी कोच नियुक्त करेगा। बता दें कि पूर्व विश्व रिकार्ड धारक 59 वर्षीय जर्मन हॉन का अनुबंध टोक्यो ओलंपिक तक ही था।एएफआई अध्यक्ष आदिल सुमरिवाला ने कहा, 'हम दो नए कोच की नियुक्ति करने जा रहे हैं तथा हम उवे हॉन को बदल रहे हैं क्योंकि हम उनके प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। हम तूर (गोला फेंक के एथलीट ताजिंदरपाल सिंह तूर) के लिए भी विदेशी कोच देख रहे हैं।'सुमरिवाला महासंघ की कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में एएफआई की योजना समिति के अध्यक्ष ललित भनोट और उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जार्ज ने भी हिस्सा लिया।

बता दें कि हॉन को ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दो अन्य एथलीटों शिवपाल सिंह और अनु रानी जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए नवंबर 2017 में एक साल के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। चोपड़ा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल 2018 में उनकी निगरानी में खेले लेकिन इसके बाद जर्मनी के ही क्लॉस बार्टोनीज यह भूमिका निभाने लगे थे।

गौरतलब है कि हॉन ने ओलंपिक से पहले यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और एएफआई ने अनुबंध स्वीकार करने के लिए उन्हें 'ब्लैकमेल' किया था। दोनों संस्थाओं ने हालांकि इस आरोप को खारिज कर दिया था।

स्मृति मंधाना ने सीरीज से पहले भरी हुंकार, बोलीं- टी-20 विश्व कप फाइनल में हार के बाद मजबूत हुई टीम इंडिया

सिडनी। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले बयान दिया है। उनका कहना है की बीते साल टी-20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद टीम में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी क्रिकेट सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगी। इस दौरे पर टीम इंडिया तीन एकदिवसीय मैच, एक डे/नाइट टेस्ट और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। इस श्रृंखला का आगाज 21 सितंबर से होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें आखिरी बार साल 2020 टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मेलबर्न में खेली थीं। इस खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 85 रनों से हराया था। द स्कूप पॉडकास्ट से बात करते हुए स्मृति मंधाना ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली विश्व कप फाइनल में हार के बाद टीम के प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है।

टीम इंडिया ने पूरा किया क्वारंटीन

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय महिला टीम ने 14 दिनों

का निर्धारित क्वारंटीन सोमवार को पूरा कर लिया।

स्मृति ने आगे कहा, टी20 विश्व कप के बाद कोविड-19 एक बड़ा ब्रेक था और बहुत सारी लड़कियों को वापस जाने और अपने खेल के बारे में अधिक समझने का मौका मिला, जो व्यक्तिगत रूप से उनकी कमी थी वे अधिक मजबूत होकर वापस आई हैं। इस स्टाइलिश खिलाड़ी ने आगे कहा, कोरोना ब्रेक के बाद भारतीय टीम धीरे-धीरे क्रिकेट खेलने की लय में वापस आ रही है।

पूरी टीम ने फिटनेस पर किया काम

टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज ने कहा, पूरी टीम ने अपनी फिटनेस और कौशल पर काम किया है, हम अभी भी लगातार मैच खेलने की लय में आ रहे हैं, हम बीते पांच-छह महीसे क्रिकेट खेल रहे हैं और मैच की मानसिकता में वापस आ रहे हैं, उम्मीद है कि भारत के लिए आगामी सीरीज अच्छी होगी। भारतीय महिला टीम जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची है। इंग्लैंड दौरे पर भारत की कुछ महिला खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर, सनसनी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था।